

» कृषि

» विश्लेषण

» जल प्रबंधन

कुल पृष्ठ: 40

# स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रु.

आषाढ़-श्रावण 2082, जुलाई 2025



**भारत बना दुनिया का चौथा  
सबसे अधिक समानता वाला देश**

स्वदेशी गतिविधियां

# स्वदेशी बैठकें

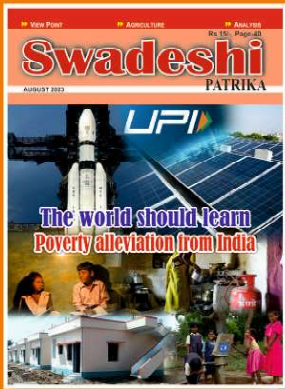
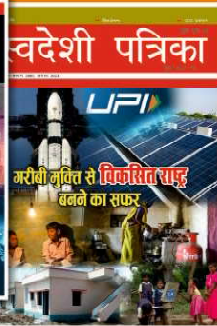
सचित्र झलक



पंचकूला (हरियाणा)



बिहार विधान परिषद



## VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

## SWADESHI

Patrika

## स्वदेशी

पत्रिका

# पढ़ें और पढ़ायें



वर्ष-33, अंक-7  
आषाढ-श्रावण 2082 जुलाई 2025

संपादक  
**अजेय भारती**

सह-संपादक  
**अनिल तिवारी**

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन  
सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग  
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022  
से प्रकाशित

दूरभाष : 011-26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ.  
अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्प्यूटेंट बाइन्डर्स  
(प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32  
से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**  
समाचार परिक्रमा **36-38**



तृतीय मुख्य पृष्ठ  
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ

**39**  
**40**

आवरण कथा - पृष्ठ-06

भारत बना दुनिया  
का चौथा सबसे  
अधिक समानता  
वाला देश

डॉ. अश्वनी महाजन



- 1 मुख्य पृष्ठ
- 2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ
- 08 अतुल्य भारत  
स्वदेशी सैन्य तकनीकी और नवाचार  
..... डॉ. धनपत राम अग्रवाल
- 12 आजकल  
भारत और ब्रिटेन ने किये मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर  
..... अनील तिवारी
- 14 दृष्टिकोण  
दुर्लभ खनिजों पर राष्ट्रीय प्राथमिकता  
..... विनोद जौहरी
- 16 समीक्षा  
कट्टरपंथ से डरा न्याय, तुष्टीकरण में फंसा देश  
..... अजय कुमार
- 18 बक्स बैटक  
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सहमति नहीं शक्ति से हासिल होगी स्थाई सदस्यता  
..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र
- 21 योग  
प्राचीन परंपराओं को समेटे आधुनिक युग का योगा  
..... संजय सक्सेना
- 23 आर्थिकी  
अमेरिका पर ही भारी पड़ सकता है टैरिफ युद्ध  
..... प्रहलाद सबनानी
- 25 ग्रामीण विकास  
भारत की ग्रामीण क्रांति ने वैश्विक विकास को कैसे परिभाषित किया  
..... विजय गर्ग
- 27 स्वास्थ्य  
दवा के बाजार में दर्द का व्यापार  
..... शिवनंदन लाल
- 29 आर्थिकी  
रिपोर्ट के आईने में भारत की विकास गाथा  
..... अन्नू कुमारी
- 31 मन की बात  
प्रधानमंत्री ने की स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील  
..... स्वदेशी संवाद
- 33 समाज  
कांटों भरी है महिला रेजिडेंट डॉक्टरों की राह  
..... वैदेही

## पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक खानपान और फैशन पर ग्लोबल कंपनियों का असर

पूर्वोत्तर भारत में हाल के वर्षों में ई-कॉमर्स कंपनियों और आधुनिक उपभोक्तावाद में तेजी से वृद्धि हुई है। 'अमेजन, फ्लिपकार्ट और म्यंत्रा' जैसी कंपनियों ने गुवाहाटी, शिलांग जैसे शहरों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में ई-रिटेल की पैठ अब राष्ट्रीय औसत से '1.2 गुना अधिक' है, जो यहां ऑनलाइन शॉपिंग और ग्लोबल ब्रांड्स की लोकप्रियता को दर्शाता है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और ग्लोबल कंपनियों की आक्रामक डिजिटल मार्केटिंग ने इस बदलाव को और तेज किया है।

'पेप्सी और कोका-कोला' जैसी फूड और बेवरेज कंपनियों ने भी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। इनके उत्पाद अब छोटे कस्बों और गांवों में भी आसानी से उपलब्ध हैं और सोशल मीडिया पर चल रहे प्रचार अभियानों के कारण युवाओं में पैकेज्ड ड्रिंक और स्नैक्स की मांग बढ़ गई है। इससे पारंपरिक स्थानीय खानपान पर असर पड़ा है।

फैशन के क्षेत्र में 'म्यंत्रा' और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म ने वेस्टर्न कपड़ों को लोकप्रिय बना दिया है, जिससे पारंपरिक कपड़ों और स्थानीय वस्त्र उद्योग की मांग में गिरावट आई है। इससे न सिर्फ स्थानीय कारीगरों की आजीविका प्रभावित हो रही है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी कमजोर हो रही है।

एक और चिंता की बात यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा, बार-बार मिलने वाली सेल और आसान क्रेडिट विकल्पों के कारण यहां के लोग, खासकर युवा, अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने लगे हैं। इससे न सिर्फ अनावश्यक खर्च और कचरा बढ़ रहा है, बल्कि कई परिवारों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ गया है।

संक्षेप में, ग्लोबल कंपनियों और आधुनिक उत्पादों ने पूर्वोत्तर भारत के उपभोक्ताओं को सुविधा और विविधता तो दी है, लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक खानपान, पहनावे और समझदारी से खर्च करने की आदतों को भी नुकसान पहुँचाया है। चुनौती यह है कि आधुनिकता और स्थानीय संस्कृति व आर्थिक संतुलन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?

विजित कुमार, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

### संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्,  
नयी दिल्ली-110022

दूरभाष : 011-26184595 • ई-मेल:

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क 'स्वदेशी पत्रिका' दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

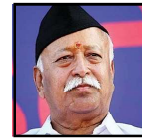
यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

## कहा-अनकहा



एक मजबूत एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि देश के सतत आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। ये उद्यम अपेक्षाकृत कम पूँजी लागत पर अधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उद्यम ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार पैदा करते हैं।

द्रोपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, भारत



स्वदेशी का आचरण लाने के लिए भाषा, भूषा भजन, भवन, भ्रमण और भोजन अपना होना चाहिए।

डॉ. मोहन भागवत, सरसंघचालक, संघ



चंद्रयान की सफलता के बाद, भारत के बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति जुनून बढ़ा है। शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक यात्रा से संकल्प को और मजबूती मिली है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत



आतंकवाद का प्रत्येक कृत्य आपराधिक और अनुचित है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे वह कहीं भी हो, और किसी के द्वारा भी किया गया हो।

राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री, भारत



भारत में गरीबी में कमी आई है, चाहे वह चरम पर हो या बहुआयामी। यह तथ्य गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण में भी उभर कर आया है।

डॉ. अश्वनी महाजन, अ.भा.सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

## कहानी भारतीय समोसे और जलेबी की

हाल ही में भारत का समोसा और जलेबी, जो लगभग पूरे देश में सर्वसुलभ हैं और पसंद किए जाते हैं, सोशल मीडिया में खासी चर्चा में रहे। इसका कारण था, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव का वह पत्र, जिसमें उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्होंने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को अनुरोध किया था कि वे सार्वजनिक स्थानों जैसे कैफेटेरिया (कैंटीन) और लॉबी में 'आयल और शुगर बोर्ड' लगाएं, जिसमें समोसे, जलेबी, बड़ा पाव, कचोरी छिपी हुई वसा और चीनी को उजागर करें। उसके बाद सोशल मीडिया में इसकी भारी आलोचना शुरू हो गई। सोशल मीडिया में भारतीय समोसे का महिमा मंडन उससे पहले कभी इस प्रकार से नहीं हुआ होगा, जितना उसके बाद हुआ। हालांकि मंत्रालय ने बाद में स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि यह निर्देश किसी खास वस्तु पर केंद्रित नहीं था। समझ सकते हैं कि फास्ट फूड में एक समस्या होती है कि लोगों को लुभाने के लिए निर्माता उसमें आवश्यकता से अधिक नमक, चीनी और फैट डाल देते हैं। इन तत्वों की अधिकता के कारण तरह-तरह की असंक्रमणकारी बीमारियां, यानी नॉन कम्यूनिकेबल डिजीस होती हैं। हृदय रोग उच्च रक्तचाप, डायबिटीज समेत एडी कई बीमारियां, लोगों के स्वास्थ्य पर ही नहीं, आर्थिक स्थिति पर भी भारी प्रतिकूल असर डालती हैं। स्वास्थ्य सचिव की एडवाइजरी में फास्ट फूड का जिक्र करते हुए, समोसे जलेबी का पहला उदाहरण देना कुछ अटपटा है। वास्तव में असंक्रमणकारी रोगों (एनसीडी) के कारण के नाते जिन फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड का अक्सर जिक्र आता है, उनमें पिज्जा, बर्गर, चाईनीज, नूडल, पेय, पोटेटो चिप्स आदि तो उसमें अक्सर शामिल किये जाते हैं, लेकिन भारत के समोसे और जलेबी का कभी भी जिक्र नहीं होता। देखा गया है कि इन फास्ट फूड में अत्यधिक मात्रा में नमक, चीनी और वसा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इन चीजों की लत लोगों में खास तौर पर बच्चों में लग जाये। स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा अक्सर इसके बारे में चिंता भी व्यक्त की जाती रही है। समझना होगा कि परम्परागत रूप से सड़क पर चलने वाले आम आदमी से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति, अफसर और नेता समोसे और जलेबी का लुत्फ उठाते देखे जा सकते हैं। देश में हर जेब के लिए समोसा उपलब्ध है। दो रुपये से लेकर 200 रुपये तक आप समोसा खरीद सकते हैं। जलेबी का तो यह आलम है कि देश में हर खुशी का इजहार जलेबी से होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार वास्तव में विशेषज्ञों की तमाम सिफारिशों के बावजूद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जरूरत से कहीं अधिक वसा, नमक और चीनी से युक्त उत्पादों के बारे में वार्निंग सिग्नल देने वाले निर्देश देने वाला आदेश अभी तक जारी नहीं कर पायी है। गौरतलब है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा बनाये जा रहे पैकेज्ड फूड में इन प्रकार के उत्पादों की भरमार है, जिसके कारण बड़ी-बड़ी एनसीडी हो रही हैं, जिस पर सरकार का ही नहीं बल्कि आम समाज का भी भारी खर्च हो रहा है। और लाखों लोगों की मौत का वह कारण बन रही है।

गौरतलब है कि भारत के खाद्य नियामक संस्थान एफएसएसआई ने दो वर्ष पूर्व एक प्रस्ताव रखा था कि देश के पैकेज्ड फूड को स्टार रेटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। जिसमें एक स्टार से लेकर पांच स्टार तक रेटिंग करने का प्रावधान रखने का प्रस्ताव था। एक स्टार यानि स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक और पांच स्टार का मतलब स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। मजेदार बात यह थी कि इसमें किसी भी उत्पाद पर कोई चेतावनी देने का प्रावधान नहीं बताया गया था। ऐसे में विशेषज्ञों द्वारा इस प्रस्ताव पर यह कहकर आपत्ति दर्ज कराई गई कि स्टार रेटिंग के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों को भी स्टार रेटिंग दी जाएगी और उपभोक्ता को यह जानकारी नहीं होगी कि वे खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं। विशेषज्ञों ने यह कहा कि अधिकांश पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में अत्यधिक वसा, नमक और चीनी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन खाद्य पदार्थों के निर्माता इन हानिकारक इंग्रीडिएंट को इसलिए डालते हैं ताकि उपभोक्ताओं को इसकी लत पड़ जाए। विशेषज्ञों ने यह मांग की कि स्टार रेटिंग की प्रक्रिया को रोक कर वार्निंग सिग्नल देने का प्रावधान रखा जाए। यानि उपभोक्ताओं को यह जानकारी हो कि वे उत्पाद अधिक वसा, नमक और चीनी के कारण हानिकारक हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के हस्तक्षेप से स्टार रेटिंग के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाला गया और उसके स्थान पर यह प्रस्ताव लाया गया कि इन हानिकारक अवयवों को पैकेज्ड पैकेट पर बड़े शब्दों में लिखा जाए। ऐसे में पैकेज्ड फूड के बारे में अब लोगों को अब कम से कम यह जानकारी मिलने लगी है कि उनमें कितने हानिकारक पदार्थ हैं। समझना होगा कि पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया को छोड़ किसी भी देश में स्टार रेटिंग का प्रावधान नहीं है; शेष दुनिया में यहाँ जहाँ पैकेज्ड फूड पर लेबलिंग का प्रावधान है, वहाँ वार्निंग सिग्नल जरूर दिए जा रहे हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय के इस पत्र और एडवाइजरी के बाद एक नई बहस छिड़ी है कि क्या हमारे सरकारी विभाग इस बात से अंजान हैं कि भारत के पुराने और ताजे स्नैक्स, पैकेज्ड फूड के मुकाबले कहीं ज्यादा स्वास्थ्यकारी हैं। यदि स्वास्थ्य मंत्रालय को तेल की गुणवत्ता के बारे में बात करनी हो तो उस प्रकार की एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी, न कि समोसे और जलेबी को चिन्हित करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर उसके बारे में चेतावनी देने की। यहां प्रश्न यह है कि अत्यधिक वसा, नमक और चीनी वाले पैकेज्ड फूड जो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनपर स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एफएसएसआई अभी तक चेतावनी जारी करने का फैसला नहीं ले पाया है। हानिकारक पैकेज्ड फूड को बचा कर, देसी समोसे और जलेबी पर गाज क्यों?

# भारत बना दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश

हाल ही में जारी विश्व बैंक की 'स्पिंग 2025 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' ने दुनिया में एक बहस शुरू की है। बहस का मुद्दा यह है कि क्या भारत वास्तव में दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है? वास्तव में देश और दुनिया में प्रचलित विमर्श का यह रिपोर्ट खंडन करती है। देश में बड़ी तादाद में बुद्धिजीवी जो इससे पूर्व की रिपोर्टों और आंकड़ों का हवाला देते हुए यह तर्क देते रहे हैं कि देश में आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ असमानताएं भी बढ़ी हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ी है, वंचित वर्ग के हालात पहले से अधिक बिगड़े हैं और यह असमानता आय और संपत्ति दोनों में दिखाई देती है। ऐसे में यदि कोई रिपोर्ट यह कहे कि देश में असमानताएं कम हुई हैं तो असमंजस स्वाभाविक ही है। ऐसे में उन बुद्धिजीवियों द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट पर प्रश्नचिन्ह लगाना भी स्वाभाविक ही है।

लेकिन यहां यह भी सत्य है कि जो लोग यह मानते हैं कि देश में आय और संपत्ति की असमानताएं बढ़ी हैं, वे भी आंकड़ों के आधार पर अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं और जो रिपोर्ट विश्व बैंक ने प्रकाशित की है, वह भी आंकड़ों पर ही आधारित है। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल है, जैसा उसके आलोचक दावा करते हैं या उसमें कुछ सच्चाई है। और यदि यह सच है तो यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में समानताएं घटने के पीछे प्रमुख कारण क्या हैं?



असमानताओं का आकलन करने वाले घरेलू सर्वेक्षणों की कमियों और कमजोरियों को तो समझा जा सकता है, लेकिन गरीबी में निश्चित रूप से कमी आई है, चाहे वह चरम पर हो या बहुआयामी।  
— डॉ. अश्वनी महाजन

## आय और संपत्ति की असमानताएं

असमानताओं को मापने का सर्वाधिक उपयोगी तरीका गिनी चटांक माना जाता है। गिनी चटांक शून्य से एक तक होता है, जहां शून्य गिनी सह गुणांक पूर्णतः समानता को और एक पूर्णतः असमानता को दर्शाता है।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और अन्य गृहस्थ आय सर्वेक्षणों के आंकड़ों के अनुसार 2023 में आय गिनी सह गुणांक 0.410 था जो 1955 में 0.371 से भी अधिक था। यदि संपत्ति के वितरण के बारे में विचार करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2023 में यह सह गुणांक 0.405 था जो 1955 में 0.341 से कहीं अधिक था जबकि शहरी क्षेत्र में यह 1955 में 0.392 से घटकर 2023 में 0.382 ही रह गया लेकिन अभी भी यह काफी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है।

## लेकिन घट गई है उपभोग में असमानताएं

भारत में आय और संपत्ति में बढ़ती असमानताओं के बीच, अच्छी खबर यह है कि उपभोग में असमानताएं कम हो रही हैं। इसे अलग-अलग शब्दों में पहले यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में भारी कमी और बाद में विश्व बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में अत्यधिक गरीबी में बड़ी कमी दर्ज की गई है। हालाँकि अत्यधिक गरीबी की परिभाषा 2.15 डॉलर प्रतिदिन से बदलकर 3.0 डॉलर प्रतिदिन

कर दी गई है, फिर भी 2022-23 में केवल 5.3 प्रतिशत लोग ही अत्यधिक गरीबी से पीड़ित थे। दिलचस्प बात यह है कि 2011-12 में यह आँकड़ा 27.1 प्रतिशत था। और यदि इस परिभाषा को पहले की तरह 2.15 डॉलर ही रखा जाए, तो 2022-23 में अत्यधिक गरीबी से पीड़ित लोगों का प्रतिशत केवल 2.3 प्रतिशत ही रह गया है।

विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में उपभोग में असमानताएँ अब कम हो गई हैं। एक अधिक समतापूर्ण समाज की ओर भारत की यात्रा पिछले कुछ वर्षों में उसके गिनी सूचकांक में परिलक्षित होती है। 2011 में यह सूचकांक 28.8 था, जो 2022 में 25.5 तक पहुँच गया। इसका मतलब है कि अब यूएनडीपी से लेकर विश्व बैंक तक, सब में इस बात पर आम सहमति है कि भारत में उपभोग असमानताएँ निश्चित रूप से कम हुई हैं।

लेकिन दूसरी ओर आलोचक भारत में बढ़ती असमानताओं का तर्क आगे बढ़ा रहे हैं, वे इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि गरीबी और उपभोग में समानताएँ दोनों पहले से कम हो गए हैं।

### क्या कहते हैं आलोचक?

आलोचकों का पहला तर्क यह है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आँकड़ों पर आधारित है और इसमें आय और संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है। उपभोग आधारित गिनी सहगुणांक असमानताओं को कम करके आंकता है, क्योंकि अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं। उसके मुकाबले आय आधारित समानताएँ अधिक विस्तृत अवधारणा है और उस संदर्भ में भारत में आय और संपत्ति की असमानताएँ वास्तव में बढ़ी है। आलोचकों का दूसरा तर्क

यह है कि विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया गया सर्वेक्षण उपभोग को ठीक प्रकार से आकलन नहीं कर पाया। ऊपर के पाँच प्रतिशत अमीर सामान्य सर्वेक्षण में अपने उपभोग को कम करके बताते हैं और उस आधार पर निष्कर्ष सही नहीं होगा।

आलोचकों का यह भी कहना है कि 2011-12 और 2022-23, जिन दो वर्षों के बीच तुलना की गई है उनकी क्रियाविधि (मेटाडोलॉजी) में काफी अंतर है इसलिए वह तुलना भी ठीक नहीं है।

आलोचकों का कहना है कि कुल 49 प्रतिशत राष्ट्रीय उपभोग को ही सर्वेक्षण में शामिल किया जा सका है, क्योंकि अमीरों द्वारा अपने उपभोग को कमतर बताया जाता है इसलिए इसके आधार पर सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी सर्वेक्षण सभी पहलुओं में परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए इन तर्कों के आधार पर हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि जब एक के बाद एक रिपोर्ट गरीबी में कमी का संकेत दे रही हैं, चाहे वह अत्यधिक गरीबी हो या बहुआयामी, उपभोग असमानताओं में कमी भी एक वास्तविकता है। भारत में वर्तमान सरकार की समावेशी नीतियों के कारण ऐसा हो सका है। पहली बार इतने कम समय में ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ और शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ घरों के निर्माण से अभावग्रस्त लोगों का जीवन बदला है। इसके साथ ही सभी घरों में बिजली, अधिकांश आबादी को पाइप से जल कनेक्शन और स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन की उपलब्धता, साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक सीमा से कम आय वाले प्रत्येक पात्र परिवार को पाँच लाख रुपये तक की मुफ्त द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाएँ, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों को गरीब बनाने वाले कारकों को समाप्त

कर रहे हैं। इसके साथ ही, हम यह भी देखते हैं कि पहले भी सरकारें समाज के गरीब तबके के उपभोग में सुधार के नाम पर भारी धनराशि खर्च करती थीं, लेकिन खामियों के कारण भारी भ्रष्टाचार और लीकेज होता था। लेकिन शून्य बैलेंस वाले 53 करोड़ से ज़्यादा जन धन बैंक खाते खोलने और इन सभी खातों को आधार व मोबाइल नंबर से जोड़ने से, बिना किसी लीकेज के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संभव हुआ। इससे न केवल सरकार का खर्च कम हुआ, बल्कि लोगों के उपभोग मानकों में सुधार लाकर उनके जीवन में निश्चित सुधार हुआ है। इसलिए, असमानताओं का आकलन करने वाले घरेलू सर्वेक्षणों की कमियों और कमज़ोरियों को तो समझा जा सकता है, लेकिन गरीबी में निश्चित रूप से कमी आई है, चाहे वह चरम पर हो या बहुआयामी। यही बात गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) में भी दिखाई देती है, जो उपभोग असमानताओं में कमी दिखाती है। लेकिन इसे अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हालाँकि असमानताएँ कम हुई हैं, लेकिन असमानताओं में कमी का श्रेय सरकारी सहायता और कुछ हद तक मुफ्त सुविधाओं को जाता है; लेकिन हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार अनंत काल तक गरीबों और वंचितों का समर्थन करती रहेगी। दीर्घकाल में, हमें लोगों को इतना सक्षम बनाना होगा कि वे अपने परिवारों की ज़रूरतें पूरी कर सकें, जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, पानी आदि। लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना होगा और देश में विकेंद्रीकरण के आधार पर छोटे व्यवसायों और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि हम वितरण में अपेक्षित समानता के दीर्घकालीन उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। □□

# स्वदेशी सैन्य तकनीकी और नवाचार

पिछले कुछ वर्षों से भारत निरन्तर सैन्य तकनीकी क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और स्वदेशी अस्त्र-शस्त्र और हथियारों के नये अनुसंधानों द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है जो हाल के भारत-पाक (सिंदूर) युद्ध में सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत सरकार के दो प्रमुख अनुसंधान केंद्र डीआरडीओ तथा इसरो के संयुक्त प्रयास से दूर मार करने वाली मिसाइलें और सेटलाइट द्वारा संचालित नाविक जैसे संवाद और अमेरिकी जीपीएस सिस्टम से भी ऊच्च स्तर के संयंत्रों और ब्राह्मोस तथा आकाशतीर जैसी अचूक निशाने वाली और जल, थल, नभ तीनों से मार करने की क्षमता वाली युद्ध कौशल में निपुण हमारी सेना राष्ट्र सुरक्षा का अभेद्य कवच और शूर-वीरता की पहचान है।

भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में बने सैन्य विमान जिनमें जासूसी विमान भी शामिल हैं तथा तेजस जैसा स्वदेशी निर्मित एवं आधुनिक हथियारों से लैस लड़ाकू विमानों ने चीन तथा तुर्की से बने विमानों और प्रेक्षास्त्रों की धज्जियाँ उड़ा दी तथा आतंकी ठिकानों को शीघ्र ही ध्वस्त कर पाकिस्तान के सैनिकों और उनके विदेशों से आयातित हथियारों को ब्राह्मोस और आकाशतीर मिसाइलों द्वारा नाकों चने चबवा दिये।

आज के वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के युग में युद्ध के शस्त्र और तरीकों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अब युद्ध आमने सामने सैनिकों से बन्दूक और तोपों से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से तकनीक पर आधारित हैं। अभी हाल ही में हमने देखा 22 जून की सुबह भारतीय समय 6.40 पर अमेरिकी जासूसी विमानों ने जिन्हें बी-2 बॉम्बर कहा जाता है वे दुनिया के सबसे खतरनाक जीबीयू-57, जिसके एक बम का वजन 13600 किलो या 3000 पाउंड होता है, ऐसे 14 बमों का इस्तेमाल कर ईरान के तीन नाभिकीय अनुसंधान केंद्रों, फोर्डो, नतांज और इस्फ़हान की पहाड़ी और पथरीली जमीन के नीचे लगभग 100 मीटर गहराई में जाकर 18 घंटों की लंबी यात्रा कर, उन पाताल में छिपे ठिकानों पर हमला करके उन्हें



भारत को 2047 के पहले एक वैभवशाली, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए स्वदेशी को पूर्णरूप से अपनाना होगा, ताकि स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी पूंजी तथा स्वदेशी शस्त्रागार एवं स्वदेशी उत्पादों के क्षेत्र में भारत स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बन सके।

— डॉ. धनपत राम  
अग्रवाल



चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी या भनक ईरान के किसी भी रक्षा कवच और राडारों को नहीं मिली जबकि अमरीकी सैन्य विमानों का काफिला 100 से ज़्यादा का था।

भारत की सैन्य शक्ति अभी हाल के वर्षों में काफ़ी तीव्रता से बढ़ी है और हम दुनिया की किसी भी शक्ति का डटकर मुकाबला करने को तैयार हैं, फिर भी हमें आज अपनी सैन्य तकनीक का जिसमें ड्रोन, मिसाइलें, स्टील्थ यानि जासूसी तथा दुश्मन के राडारों से अपनी पहचान को छिपाकर उड़ने वाले विमान तथा आधुनिक अस्त्र शस्त्र से संपन्न विमान जिनमें राफेल जैसे विमान शामिल हैं, इस तरह की तकनीक का अनुसंधान करने की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं तथा उनमें जो कमी है, उसे दूर करने का प्रयास भी जारी है।

ऐसी स्थिति में दुश्मन देशों के पास जिस तरह की आधुनिक और अत्याधुनिक तकनीक है, उसका अवलोकन और विश्लेषण भी आवश्यक है और हमारी सैन्य सुरक्षा के लिये धन की भी आवश्यकता है। इन सारी बातों को समझने से पहले हमें अपनी वर्तमान स्थिति की समीक्षा करनी चाहिये।

भारत की सैन्य सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक अनुसंधान की मौजूदा स्थिति, उपलब्धियाँ और चुनौतियों पर तथ्यों सहित एक समीक्षा में हम पाते हैं कि 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति संतुलन में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। एशिया-प्रशांत क्षेत्र, हिन्द महासागर और दक्षिण एशिया में सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने अपनी सैन्य सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

भारत की सशस्त्र सेनाएँ जो एक त्रिशूल के रूप में हमारी सीमाओं की रक्षा करती हैं ये क्रमशः थल सेना, वायु सेना और नौसेना विश्व की सबसे बड़ी

और सक्षम सेनाओं में गिनी जाती हैं। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। भारत के कुल सैनिकों की संख्या 14.5 लाख है जिनमें थल सेना : 12.3 लाख सक्रिय वायु सेना : 1.4 लाख नौसेना : 72,000 (2024 तक)।

आज के युद्ध के तरीके पारम्परिक नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकी से युक्त होते हैं और जिनमें निरंतर तेज़ी से बदलाव हो रहा है। भारत अपनी सैन्य क्षमता को तकनीकी रूप में मिसाइल, लड़ाकू विमान एवं अंतरिक्ष उपग्रहों द्वारा संचालित नाविक जैसी संचार तकनीकों के आधार पर सूक्ष्म से सूक्ष्म ठिकानों पर सटीक निशाने से आक्रमण करने की तैयारी में अपने दुश्मन देशों से भी उत्तम किस्म के बंकर ब्लास्टर बम भी बना रहा है जो धरती की सतह से 200 मीटर नीचे तक घात कर सकते हैं।

### ब्राह्मोस मिसाइल

भारत के पास शक्तिशाली मिसाइलों का एक प्रभावशाली शस्त्रागार है जो उसकी सामरिक रक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से, ब्राह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जो रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम है। 800 किमी तक की रेंज और 2.8–3 मैक की गति के साथ, इसे जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी सटीकता, कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता और मल्टी-रोल विशेषताएँ भारत को दुश्मन के ठिकानों, नौसैनिक जहाजों और बंकरों पर तेज़ी से हमला करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे उसकी नौसैनिक शक्ति और सामरिक प्रभाव बढ़ता है, खासकर चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने और हिंद महासागर में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण है।

**भारत अपनी सैन्य क्षमता को तकनीकी रूप में मिसाइल, लड़ाकू विमान एवं अंतरिक्ष उपग्रहों द्वारा संचालित नाविक जैसी संचार तकनीकों के आधार पर सूक्ष्म से सूक्ष्म ठिकानों पर सटीक निशाने से आक्रमण करने की तैयारी में अपने दुश्मन देशों से भी उत्तम किस्म के बंकर ब्लास्टर बम भी बना रहा है जो धरती की सतह से २०० मीटर नीचे तक घात कर सकते हैं।**

### आकाश मिसाइल

आकाश मिसाइल, एक सतह से हवा में मार करने वाली (एसएएम) मिसाइल है, जो पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। इसे कम से मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज़ मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 30–50 किमी की रेंज और 2.5 मैक की गति के साथ, यह एक महत्वपूर्ण वायु रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, जो सामरिक अड्डों, रडार प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा करती है।

### पृथ्वी मिसाइल

भारत की पृथ्वी मिसाइल एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। अपने विभिन्न संस्करणों (पृथ्वी-I, II, III) में 150–350 किमी तक की रेंज के साथ, यह सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित जवाबी हमला करने की क्षमता प्रदान करती है और भारत की रणनीतिक निवारक क्षमता का एक प्रमुख घटक है। मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई, इसे युद्धकाल में दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर हमला करने

के लिए डिज़ाइन किया गया है।

### अग्नि मिसाइल

अग्नि मिसाइल श्रृंखला में सतह से सतह पर मार करने वाली इंटरकाटिमेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें (आईसीबीएम) शामिल हैं जो भारत की परमाणु त्रय की रीढ़ हैं। अग्नि-I (700 किमी) से अग्नि-V (5000-5500 किमी) और आगामी अग्नि-VI (8000-10000 किमी) तक की रेंज वाली ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। अग्नि-VI जैसे भविष्य के संस्करणों में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) तकनीक को शामिल करने की उम्मीद है, जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों पर कई वारहेड पहुंचा सकेगी। मोबाइल प्लेटफॉर्म या भूमिगत साइलो से लॉन्च की गई अग्नि मिसाइलें भारत को एक निर्णायक लंबी दूरी की मारक क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन सुनिश्चित होता है।

अंत में, के-6 मिसाइल, जो वर्तमान में विकास के अधीन है, एक पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (एसएलबीएम) है जिसकी अनुमानित रेंज 6000-8000 किमी है। अरिहंत-श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों के लिए डिज़ाइन की गई, के-6 परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम होगी और इसमें एमआईआरवी तकनीक होगी। यह मिसाइल भारत के परमाणु त्रय को पूरा करेगी, जिससे समुद्र के नीचे से एक अदृश्य दूसरी-स्ट्राइक क्षमता मिलेगी। यह क्षमता किसी भी प्रतिकूल हमलावर द्वारा संभावित पहले हमले के बाद भी निर्णायक जवाबी हमले की गारंटी देती है, जिससे हिंद महासागर में भारत का सामरिक प्रभुत्व मजबूत होता है। विशेष रूप से ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलें, भारत के

फर्स्ट यूज़; परमाणु सिद्धांत के बावजूद, मजबूत दूसरी-स्ट्राइक और जवाबी-स्ट्राइक क्षमताओं को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

### भारत के प्रमुख लड़ाकू वायुयान (2025): एक सिंहावलोकन

भारतीय वायुसेना के पास कई महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान हैं, जिनमें एचएएल तेजस (एलसीए तेजस) एक हल्का मल्टी-रोल स्वदेशी विमान है जिसकी अधिकतम गति मैक 1.6 और युद्ध भार 4000 किलोग्राम है। यह एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलों से लैस है और 2025 से इसके एमके-1ए संस्करण को शामिल किया जाएगा, जो सीमावर्ती वायु रक्षा और मल्टी-रोल स्ट्राइक में महत्वपूर्ण होगा। सुखोई-30 एमकेआई भारत का सबसे घातक और मुख्य एयर डोमिनेंस फाइटर है, जिसे एचएएल और रूस ने लाइसेंस के तहत बनाया है। यह मैक 2 की अधिकतम गति, 8000 किलोग्राम युद्ध भार और 3000 किलोमीटर की रेंज वाला एक भारी मल्टी-रोल फाइटर है, जो ब्रह्मोस-ए सहित विभिन्न मिसाइलों को ले जा सकता है। मिराज-2000, फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित एक मल्टी-रोल फाइटर है, जिसकी अधिकतम गति मैक 2.2 और रेंज 1550 किलोमीटर है। यह एमआईसीए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, साथ ही यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है।

### वायुसेना का बेड़ा और आधुनिकीकरण

रूस निर्मित मिग-29 UPG एक मल्टी-रोल फाइटर है जिसकी अधिकतम गति मैक 2.3 और ऑपरेशन रेंज 1500 किलोमीटर है, जो वायु सीमा सुरक्षा और स्ट्राइक मिशनों के लिए उपयोग होता है। जगुआर (SEPECAT Jaguar), जिसे एचएएल द्वारा लाइसेंस के तहत बनाया गया है, एक ग्राउंड अटैक

और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जिसकी अधिकतम गति 1350 किमी/घंटा और रेंज 1400 किमी है। यह लेजर गाइडेड बम और AS-30L मिसाइलों से लैस है और परमाणु क्षमता भी रखता है।

### भारत की उन्नत अनुसंधान परियोजनाएँ: भविष्य की वायु शक्ति

भारत भविष्य की वायु शक्ति के लिए कई उन्नत परियोजनाओं पर काम कर रहा है। एचएएल एएमसीए (उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान) एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी-रोल फाइटर है जो डिज़ाइन और प्रोटोटाइप निर्माण के चरण में है, जिसका लक्ष्य 2028 तक इसे शामिल करना है। इसकी अधिकतम गति मैक 2.15 होगी और इसमें स्टील्थ तकनीक, स्वदेशी ईईएसए रडार और सुपरक्रूज़ क्षमता होगी, जो इसे चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 के समकक्ष खड़ा करेगा। TEDBF (Twin Engine Deck Based Fighter) नौसेना के लिए एक स्टील्थ फाइटर है जिसे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाखापत्तनम पर संचालन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, और यह नौसेना के MiG-29K का भविष्य का विकल्प होगा। इसके अतिरिक्त, तेजस एमके-2 एक मध्यम वजन का मल्टी-रोल फाइटर है जिसका प्रोटोटाइप 2025 में तैयार होगा और 2028 से शामिल किया जाएगा। इसकी अधिकतम गति मैक 2, युद्ध भार 6500 किलोग्राम और रेंज 1700 किलोमीटर होगी, जिसमें बेहतर ईंधन क्षमता और हथियार ले जाने की क्षमता होगी।

कुल मिलाकर, एएमसीए, टीईडीबीएफ और तेजस एमके-2 जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भारत को 5वीं और 6वीं पीढ़ी की वायु प्रभुत्व शक्ति में आत्मनिर्भर बनाएंगी। 2025-2035 का दशक भारतीय वायुसेना के लिए अत्यंत

निर्णायक होगा, क्योंकि इस अवधि में स्वदेशी स्टील्थ फाइटर और आधुनिक मल्टी-रोल लड़ाकू विमानों के आगमन से भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर और भी मजबूत होगी।

### भारत की सैन्य शक्ति सुदृढ़ीकरण हेतु इसरो-डीआरडीओ का रणनीतिक समन्वय

आज के बदलते भू-राजनीतिक माहौल में युद्ध केवल ज़मीनी सीमाओं और परंपरागत रणक्षेत्र तक सीमित नहीं रह गए हैं। भविष्य में युद्ध अंतरिक्ष, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक और हाइपरसोनिक हथियारों के माध्यम से लड़े जाएंगे। इस संभावित चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत की दो अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाएँ – भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) – देश की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक तकनीकी युग के अनुरूप सशक्त करने के लिए समन्वित रणनीति पर कार्य कर रही हैं।

इस दिशा में भारत ने कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। वर्ष 2019 में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) का गठन किया गया, जो इसरो और डीआरडीओ के संयुक्त सैन्य अंतरिक्ष अभियानों, उपग्रह निगरानी और एंटी-सैटेलाइट क्षमताओं का समन्वय करती है। इसी वर्ष मिशन शक्ति के अंतर्गत भारत ने सफलतापूर्वक एंटी-सैटेलाइट परीक्षण कर अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद भारत ने IndSpaceEx नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया, जो अंतरिक्ष, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध की तैयारी को परखने का पहला समन्वित प्रयास था।

भारत ने हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। डीआरडीओ ने

हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर (एचएसटीडीवी) और इसरो ने पुनः उपयोग योग्य प्रक्षेप यान (RLV-TD) विकसित कर भविष्य की रक्षा तकनीकों में अपनी पकड़ मजबूत की है। साथ ही द्वैत्य-उपयोग उपग्रहों के माध्यम से त्वरित सैन्य निगरानी की क्षमता भी विकसित की जा रही है, जिनमें आरआईएसएटी, जीआईएसएटी और Cartosat जैसे उपग्रह शामिल हैं। भारत अब Directed Energy Weapons जैसे लेज़र और माइक्रोवेव हथियारों का भी संयुक्त रूप से विकास कर रहा है।

सुरक्षित सैन्य संचार के लिए क्वांटम संचार एवं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उपग्रह नेटवर्क की दिशा में भी इसरो और डीआरडीओ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही, अंतरिक्ष, ड्रोन, रडार और साइबर उपकरणों से प्राप्त डाटा का त्वरित विश्लेषण कर एआई आधारित निर्णय प्रणाली भी तैयार की जा रही है, जो युद्धकालीन स्थितियों में त्वरित और सटीक निर्णय लेने में सहायक होगी।

इन सभी योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए रक्षा स्पेस कमांड का गठन किया गया है, जो प्रमुख रूप से ब्रह्म के अधीन कार्य करेगा। इसके अंतर्गत इसरो-डीआरडीओ संयुक्त अनुसंधान परिषद और संयुक्त स्पेस ऑपरेशंस सेंटर (जेएसओसी) बनाए जाएंगे, जहाँ उपग्रह, हाइपरसोनिक, एआई-आईएसआर, Directed Energy Weapons और साइबर क्वांटम डाटा का समन्वित और त्वरित संचालन होगा।

सरकार ने इस समन्वित परियोजना के लिए 2025 से 2030 तक 10,000 करोड़ रुपये का 'डिफेंस स्पेस मॉडर्नाइजेशन फंड' स्वीकृत किया है। साथ ही स्पेस रक्षा प्रोटोटाइप लैब तथा फ़ज़क और हाइपरसोनिक अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।

इसरो और डीआरडीओ का यह रणनीतिक समन्वय भारत की

सुरक्षा-संप्रभुता को मजबूत करेगा और देश को 2030 तक तकनीकी युद्धों में निर्णायक बढ़त दिलाएगा। भविष्य के बहु-डोमेन युद्धों में भारत को सामरिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। इस रणनीतिक सिद्धांत को "शत्रुविनाश: भारत का एकीकृत अंतरिक्ष एवं तकनीकी युद्ध सिद्धांत" नाम दिया गया है, जो आने वाले वर्षों में देश की रक्षा नीति का आधार बनेगा।

### हमारा रक्षा बजट (2024-25):

वर्तमान वर्ष में हमारा रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रु. (जीडीपी का 2.1 प्रतिशत) है और इसमें लगातार वृद्धि की जा रही है। हालांकि यह अमेरिका के 997 बिलियन और चीन के 314 बिलियन की तुलना में काफी कम है

### उपसंहार

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत को तुलनात्मक दृष्टि से और अधिक प्रगति के लिए भारत के रक्षा बजट में बढ़ोतरी के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' परियोजना के तहत भारतीय निजी क्षेत्र तथा सरकारी सैन्य शस्त्र उत्पादन करने वाली कंपनियों को तेजी से अपने अनुसंधान और नवाचार को गति देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ डीआरडीओ तथा इसरो के द्वारा जो नयी तकनीक का विकास हो रहा है, उसे ज़मीनी स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी एवं सरकारी कंपनियों के बीच पारदर्शिता के साथ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को 2047 के पहले एक वैभवशाली, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए स्वदेशी को पूर्णरूप से अपनाना होगा, ताकि स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी पूंजी तथा स्वदेशी शस्त्रागार एवं स्वदेशी उत्पादों के क्षेत्र में भारत स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बन सके। □□

डॉ. धनपत राम अग्रवाल (अखिल भारतीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच)

भारत पर बढ़ता दुनिया का भरोसा

# भारत और ब्रिटेन ने किये मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

तीन वर्षों से अधिक अवधि की जद्दोजहज के बाद आखिरकार लंदन में भारत-ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) हो ही गया। समझौते से उत्साहित दोनों देशों की सरकारों ने समझौता को ऐतिहासिक करार दिया है। इस समझौते के तहत दोनों देश आपसी व्यापार को 2030 यानी अगले चार-पांच सालों में 120 अरब यूएस डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत और ब्रिटेन के बीच यह द्विपक्षी समझौता ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर अन्य देशों को आर्थिक मसलों पर प्रभावित और संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका अपनी सुविधा के मुताबिक फैसला लेते हुए बेलगाम शुल्क और इससे आगे पाबंदी लगाने तक की बात करता रहा है। ऐसे में यह व्यापार समझौता किस रूप में सामने आएगा, वह तो दोनों देशों के बीच भविष्य में होने वाले कार्य व्यवहार से पता चलेगा। वैसे भी दो देशों के बीच होने वाली बातचीत जब तक द्विपक्षी और सामान हित सुनिश्चित करने की नीति पर आधारित नहीं होती तब तक उसका हासिल भी कुछ ठोस नहीं निकलता।

भारत और ब्रिटेन के बीच में ताजा करार इस बात का उदाहरण है कि दो देशों के बीच एक समझौते को कैसे एक बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है। विकसित देशों की ओर से जिस तरह से अपने फायदे में शर्त आधारित संबंधों को कूटनीति का फार्मूला बनाया जाता रहा है, उसमें भारत को भी अपने हित के प्रति सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि ब्रिटेन के साथ हुए हालिया समझौते के बाद अन्य देशों के साथ चल रही व्यापार वार्ता पर असर पड़ना लाजमी है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से लंबित एफटीए वार्ता चल रही है। ब्रिटेन के साथ सफल समझौते से अब ईयू पर दबाव बढ़ेगा कि वह भी भारत के साथ जल्दी समझौता करे। यदि ब्रिटिश कंपनियां भारत में तेजी से निवेश करती हैं तो यूरोपीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान हो सकता है।

अमेरिका और भारत के बीच अब तक कोई पूर्ण एफटीए नहीं हुआ है। ब्रिटेन के साथ हुए इस समझौते को देखकर अमेरिका भारत के साथ व्यापार सहयोग को पुनर्संतुलित कर सकता है। साथ ही अमेरिका यूके के साथ अपने ट्रांस अटलांटिक व्यापार संबंधों को भारत के साथ यूके की नई निकटता के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकित कर सकता है।

भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ 'इंडस ईसीटीए' और कनाडा के साथ प्रस्तावित एफटीए वार्ता की है। यूके के साथ हुआ यह समझौता मॉडल एग्रीमेंट के रूप में पेश किया जा सकता है, जिससे भारत अन्य देशों से भी समान या बेहतर शर्तों की मांग कर सकता है।

भारत जैसे विकासशील देश का एक विकसित देश के साथ संतुलित और लाभकारी एफटीए करना दक्षिणी देशों के लिए एक प्रेरणा मॉडल बन सकता है। इससे वैश्विक दक्षिण



ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार होने से भारत के कृषि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

—अनिल तिवारी

की सौदेबाजी की शक्ति मजबूत हो सकती है और वे अपने व्यापारिक हितों को वैश्विक पटल पर अधिक मजबूती से रख सकेंगे।

ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट के बाद राष्ट्रमंडल देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। भारत के साथ यह समझौता इस दिशा में प्रारंभिक और प्रतीकात्मक सफलता है। इससे अन्य राष्ट्रमंडल देश जैसे नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया भी ब्रिटेन के साथ व्यापारिक रिश्तों में पुनर्समीक्षा कर सकते हैं।

देश के कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता एक द्विपक्षीय करार होते हुए भी बहुपक्षीय प्रभावों वाला समझौता है। यह न केवल क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा बल्कि वैश्विक व्यापार नीति, रणनीतिक साझेदारी और एफटीए मॉडलिंग की दिशा को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में इस समझौते को सिर्फ दो देशों के बीच का आर्थिक सहयोग न मानकर भविष्य की वैश्विक आर्थिक दिशा के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से संरक्षणवाद बढ़ा है, उसमें ऐसे व्यापार समझौतों की भूमिका अहम हो जाती है। इस समझौते से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल अमेरिका, बल्कि अन्य देशों को भी भारत की मजबूत होती स्थिति का आईना दिखाया है, जो उनकी दूरगामी राजनीति का द्योतक है।

इस समझौते को मौजूदा दौर में दुनिया भर में जारी बहुस्तरीय तनाव, दबाव एवं दादागिरी की राजनीति के बीच सूझबूझभरी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुल्क के मोर्चे पर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन भारत ने इस द्वंद्व के सामने झुकने की बजाय नये रास्ते खोजे हैं। निश्चित ही यह समझौता महज



कागजी करार भर नहीं है, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न को मूर्त रूप देने की ठोस रणनीति है। जहां एक ओर यह समझौता 99 प्रतिशत टैरिफ को समाप्त कर वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, कृषि और रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को नई उड़ान देगा, वहीं छोटे उद्यमों, मछुआरों और किसानों को वैश्विक मंच पर पहचान भी दिलाएगा। भारत के ग्रामीण अंचलों से हल्दी, दाल, अचार जैसे उत्पाद अब ब्रिटिश बाजारों में अपनी महक फैलाएंगे।

मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में जिस प्रकार से गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता पर जोर दिया है, उसी का परिणाम है यह करार। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि भारत अब केवल बाजार नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति भी बन चुका है। यह समझौता सेवा क्षेत्र, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, निवेश, सामाजिक सुरक्षा, और दोहरे कराधान जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयों के लिए नये द्वार खोलता है। खासकर ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए यह राहत का संदेश है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिल सकेगी। यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब तक अमेरिका की ओर से पैदा किए गए किसी भी दबाव के आगे भारत ने झुकना स्वीकार नहीं किया और उसने भारत-ब्रिटेन जैसे नये विकल्पों को खड़ा करने और पुराने को

मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मेड इन इंडिया संकल्प की दृष्टि से यह डील अहम है। इससे करीब 99 प्रतिशत निर्यात यानी यहां से ब्रिटेन जाने वाली चीजों पर टैरिफ से राहत मिलेगी। इसी तरह ब्रिटेन से आनी वाली चीजें भारत में सरस्ती मिल सकेंगी जिससे आम लोगों को अधिक गुणवत्ता वाला सामान सस्ते में सुलभ होगा और उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार होगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 2.8 प्रतिशत है, जबकि चीन की 28.8 प्रतिशत।

इसी तरह, देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 17 प्रतिशत है और सरकार इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है। इस तरह की डील से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर पर प्रदर्शन में सुधार होगा। कृषि सेक्टर को उन्नत बनाने एवं अधिक उत्पाद की दृष्टि से भी व्यापक फायदा होगा।

इस समय भारत की बातचीत अमेरिका से भी चल रही है लेकिन वहां कृषि और डेयरी प्रॉडक्ट्स को लेकर रस्साकशी है। अमेरिका इन दोनों क्षेत्रों में खुली छूट चाहता है, जबकि अपने लोगों के हितों को देखते हुए भारत ऐसा नहीं कर सकता। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार होने से भारत के कृषि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। □□

# दुर्लभ खनिजों पर राष्ट्रीय प्राथमिकता

वर्तमान वैश्विक व्यापार अवरोधों में चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति शृंखला में व्यवधान डालने के प्रयासों से भारत के विभिन्न उद्योगों में चिंता बढ़ी है जबकि स्वयं भारत विश्व के दुर्लभ खनिज भंडारों में तीसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का चीन ने दुर्लभ खनिजों की एकाधिकार वर्चस्व द्वारा ही प्रतिरोध किया है। भारत ने हाल ही में दुर्लभ खनिजों के भंडार वाले देशों के साथ समझौतों की ओर कदम बढ़ाया है और अपने देश में ही खनन और शोधन के प्रयासों को प्राथमिकता दी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नॉलजी पर आधारित आकार देने में रेयर अर्थ मिनरल्स (दुर्लभ खनिज) की बड़ी भूमिका है। रेयर अर्थ एलीमेंट्स (दुर्लभ खनिज) आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया के लिए उतने ही आवश्यक हैं, जितना मनुष्य के लिए अनाज। 17 तत्वों के इस समूह को इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर मोबाइल फोन, रक्षा उपकरण, और पवन टरबाइन जैसी हाई-टेक चीजों में प्रयुक्त होते हैं। दुर्लभ खनिजों के समूह ग्रुप में सम्मिलित सेरियम का उपयोग कार एग्जॉस्ट सिस्टम्स के कैटेलिटिक कन्वर्टर में किया जाता है और गैसोलीन में मिलाया जाता, वहीं डिस्क ड्राइव और लाउडस्पीकर्स के सुपर मैग्नेट्स में जायस्पोरियम और नियोडायमियम का इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड गाड़ियों की बैटरी और यहां तक कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक तक में इनका उपयोग होता है।

17 दुर्लभ तत्वों में सीरियम, डिसप्रोसियम, अर्बियम, यूरोपियम, गैडोलीनियम, होल्मियम, लैंथेनम, ल्यूथेशियम, नियोडिमियम, प्रेजोडायमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, स्कैंडियम, टर्बियम, थ्यूलियम, इटरबियम और अट्रियम सम्मिलित हैं। इन खनिजों में अद्वितीय चुंबकीय, ल्यूमिनेसेंट और विद्युत रासायनिक गुण मौजूद रहते हैं और इस प्रकार ये तत्व उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिये भी ये तत्व काफी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिये उच्च तापमान सुपरकंडक्टिविटी, पोस्ट-हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था के लिये हाइड्रोजन का सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा दक्षता आदि में दुर्लभ खनिजों का उपयोग सबसे आवश्यक है।

चीन आज जिस स्थिति में है, वहां वह एकाएक नहीं पहुंचा है। वर्ष 1990 के बाद से उसने इन तत्वों को रणनीतिक रूप से जरूरी माना और अपने नियमों, टेक्नोलॉजी और नीतियों को उसी के अनुसार से बदला। चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स का व्यापार बीते तीन दशकों में 9 गुना हो गया है। चीन की पर्ल नदी, जूलॉन्ग नदी, ल्याओहे नदी से लेकर पोयांग झील और डॉन्गटिंग झील तक में ये पाए जाते हैं। वर्ष 2011 तक चीन रेयर अर्थ का 90 प्रतिशत उत्पादन अकेले करता था। हालांकि, 2022 तक यह हिस्सेदारी 62.9 प्रतिशत पर आ गई थी। चीन के बाद अमेरिका, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया इनके उत्पादन में आगे हैं। चीन के 39 विश्वविद्यालयों में इस विषय पर नियमित अध्ययन होता है। इसके सापेक्ष विश्व के सबसे विकसित देश अमेरिका में एक भी पाठ्यक्रम नहीं है।

## भारत के प्रयास

इस विषय में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को एक बड़ी सफलता मिली है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि सरकारी अध्ययनों से पता चला है कि तेलंगाना के सत्तुपल्ली और रामागुंडम की खुली खदानों से निकलने वाली हर 15 टन मिट्टी



भारत दुर्लभ खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेगा और उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और इस मामले में चीन का एकाधिकार तोड़ने में भी सफलता मिलेगी।  
— विनोद जौहरी

में एक किलोग्राम स्कैंडियम और स्ट्रोंटियम जैसे कीमती खनिज पाए जाते हैं। इन खदानों से अगस्त 2025 से व्यावसायिक आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है। स्कैंडियम एक खास धातु है, जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज के पाटर्स, ईंधन सेल और स्पोर्ट्स के सामान बनाने में होता है। वहीं, स्ट्रोंटियम का उपयोग फेराइट मैग्नेट, दवा, सिरमिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुर्लभ पृथ्वी तत्व की खोज में आगे बढ़ रहा है। भारत की कोयला खदानें इसमें सहायता कर रही हैं। सरकार कोयला खदानों से निकलने वाले कचरे से रेयर अर्थ मेटल्स निकालने को बढ़ावा दे रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह खोज केवल वर्तमान खदानों तक ही सीमित नहीं है। इसे पेट्रोलियम सेक्टर और कम खोजे गए खनिज क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है। यह भारत के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का भाग है। इसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के लिए जरूरी खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनना है।

केंद्र सरकार देश में नियोडिमियम की उपस्थिति से अवगत है। खान मंत्रालय के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण, यूएनएफसी चरण अर्थात पुनरीक्षण सर्वेक्षण, प्रारंभिक अन्वेषण और सामान्य अन्वेषण और खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) (एमईएमसी) नियम, 2015 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए देश भर में खनिज अन्वेषण में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम, 2023 में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण खनिजों सहित विभिन्न खनिज वस्तुओं के लिए संसाधन बढ़ाना है। फील्ड सीजन (एफएस) 2021-22 और 2022-23 के दौरान, जीएसआई ने अनुमोदित फील्ड सीजन कार्यक्रम के

अनुसार राजस्थान के सिरौही और भीलवाड़ा जिलों में नियोडिमियम सहित दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए तीन पुनरीक्षण चरण परियोजनाएं शुरू की थीं।

भारत में रेयर अर्थ एलीमेंट्स के रिजर्व खोजने में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हाल के वर्षों में कुछ सफलता मिलती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आयात के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो वर्ष 2019-20 में हम 1448 टन रेयर अर्थ एलीमेंट्स का आयात कर रहे थे जो 2023-24 तक 2270 टन पर पहुंच गया। वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा आयात चीन से किया गया जबकि हॉन्ग-कॉन्ग, जापान, मंगोलिया, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और फ्रांस भी बड़े आपूर्तिकर्ता रहे।

इसी वर्ष सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन प्रारम्भ किया है जो इन अत्यावश्यक मिनरल्स में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर लक्षित है। इसके अंतर्गत जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वित्तीय वर्ष 2025 से वित्तीय वर्ष 2031 तक 1200 एक्सप्लोरेशन प्रॉजेक्ट्स का लक्ष्य दिया गया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत देश और विदेश में क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स को प्राप्त करने, वैल्यू चेन को सुदृढ़ करने के लिए कौशल विकास, मिनरल प्रोसेसिंग पार्क, पेटेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी।

भारत में 1963 से अटॉमिक एनर्जी विभाग के अंतर्गत रेयर अर्थ के उत्पादन का दायित्व 1950 में गठित इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आई आर ई एल इंडिया लिमिटेड) को मिला है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी वार्षिक क्षमता 6 लाख टन की है। यह इल्मेनाइट, यूटाइल, जिरकॉन, सिलिमैनाइट और गार्नेट जैसे अहम मिनरल्स का उत्पादन करता है। इसका एक प्लांट ओडिशा में और रिफाइनिंग यूनिट केरल में है।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान के बालोतरा (पूर्ववर्ती बाड़मेर) जिले के

कुछ हिस्सों में कठोर चट्टानी क्षेत्रों में 1,11,845 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड (आरईओ) की खोज की है। दुर्लभ मृदा धातुओं सहित महत्वपूर्ण खनिजों के उपयोग हेतु नीतिगत ढाँचे के रूप में, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन प्रारम्भ किया गया है, जो घरेलू महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन और विदेशी आपूर्ति स्रोतों को बढ़ाकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने की भारत की रणनीतिक पहल है।

रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे खनिज हैं, जो विश्व के ग्रीन और डिजिटल भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। क्वाड देशों — भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मदद से भारत रेयर अर्थ मेटल्स की खोज, उत्पादन और प्रोसेसिंग को आगे बढ़ा सकता है। इससे भारत दुर्लभ खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेगा और उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और इस मामले में चीन का एकाधिकार तोड़ने में भी सफलता मिलेगी। अभी 1 जुलाई, 2025 को वाशिंगटन डीसी में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसका मकसद लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों के लिए सुरक्षित और मजबूत सप्लाई चेन तैयार करना है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वॉंग और जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया शामिल हुए थे। आज के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिज बहुत जरूरी हैं। दरअसल, जैसे-जैसे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल तकनीक की ओर बढ़ रही हैं, इन खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे ही प्रयासों के चलते भारत निकट भविष्य में दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण एवं उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा। □□

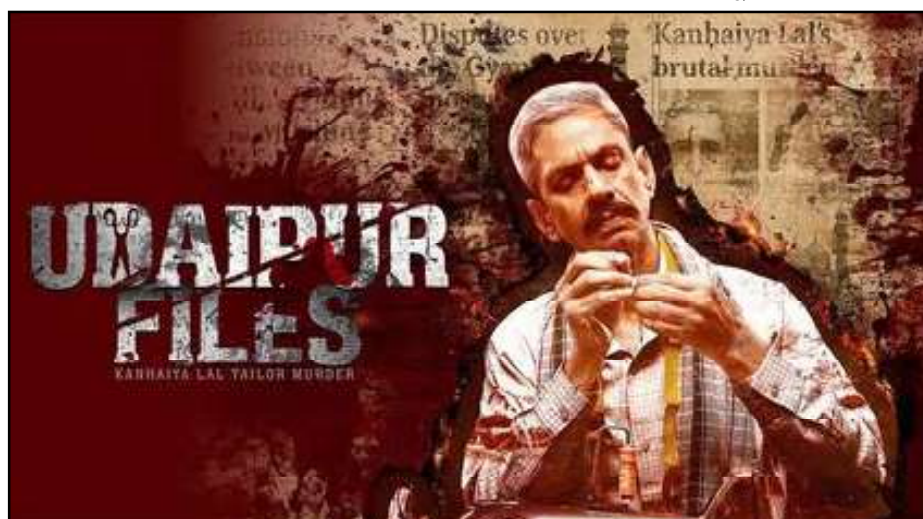
# कट्टरपंथ से डरा न्याय, तुष्टीकरण में फंसा देश

‘उदयपुर फाइल्स’ पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक ने एक बार फिर भारत की न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था की रीढ़ पर सवाल खड़ा कर दिया है। यह फिल्म 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल तेली की नृशंस हत्या पर आधारित है। एक दर्जी की हत्या, जो केवल एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हुई, और वह पोस्ट भी उसका नहीं था उसका 8 वर्षीय बेटा गलती से उसे फॉरवर्ड कर बैठा था। इस पूरी त्रासदी को तीन साल हो गए, लेकिन इंसाफ अब तक अटका हुआ है। वहीं, उस पर बनी फिल्म को कोर्ट ने तीन दिन में रोक दिया। क्या यह विरोधाभास नहीं है? फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली थी। 150 से अधिक कट्स लगाए गए। धार्मिक स्थलों और संगठनों के नाम हटाए गए, नूपुर शर्मा का नाम हटाया गया। पूरी कोशिश की गई कि किसी समुदाय को आहत न किया जाए, फिर भी विरोध हुआ। और विरोध भी किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद नाम की उस संस्था ने किया जिसकी पृष्ठभूमि खुद विवादों से भरी पड़ी है। कोर्ट ने ट्रेलर और याचिका के आधार पर फिल्म पर अंतरिम रोक लगा दी और केंद्र से रिपोर्ट मांग ली।

यही जमीयत उलेमा-ए-हिंद है, जिसने पिछले दो दशकों में 700 से अधिक आतंकवाद के आरोपियों को कानूनी मदद दी है। 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, 26/11 का मुंबई हमला, मालेगांव विस्फोट, वाराणसी सीरियल धमाके, दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट, अहमदाबाद बम धमाके जिन घटनाओं ने पूरे देश को दहला दिया, जिनमें सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारे गए, उनमें भी यह संस्था आतंक के आरोपियों की तरफ खड़ी दिखी। कोर्ट में उनके पक्ष में बहस करने के लिए वकील खड़े किए गए, हर कानूनी रास्ता उन्हें राहत दिलाने के लिए अपनाया गया। उत्तर प्रदेश में अल-कायदा के दो संदिग्ध आतंकियों को भी यही जमीयत वकील उपलब्ध करवाती है। 2022 में जब अहमदाबाद धमाकों में 49 आतंकियों को दोषी ठहराया गया, तब भी उनके बचाव में जमीयत के वकील कोर्ट में मौजूद थे। यह कहकर



‘उदयपुर फाइल्स’ भले अभी रुकी हो, लेकिन जिस दिन वह फिर सामने आएगी, तब सवाल और तीखे होंगे, और जवाब देना और कठिन हो जाएगा। क्योंकि जब आप सच्चाई से भागते हैं, तो वो और तेज़ी से आपका पीछा करती है।  
— अजय कुमार



कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, यह संस्था वर्षों से उन चेहरों को कानूनी सुरक्षा देती रही है, जिन पर दर्जनों लाशों का खून चिपका है। और अब जब एक फिल्म उन आतंक की घटनाओं की मानसिकता को बेनकाब करने की कोशिश करती है, तो यही संस्था कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उस पर रोक लगाने की मांग करती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या किसी संगठन को कोर्ट जाना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि आखिर एक फिल्म से इतना डर क्यों? किसे डर है कि कहीं सच सामने न आ जाए? क्या ये वही सच है जिसे अदालतों में बरसों तक घसीटने की कोशिश की जाती है, लेकिन पर्दे पर आते ही असहनीय लगने लगता है? और जब ये संस्था एक फिल्म को 'सांप्रदायिक' बताकर उसे जनता तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करती है, तो उसकी नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है क्योंकि उसका अतीत सिर्फ इंसाफ की लड़ाई नहीं, कई बार सच्चाई को धुंधलाने की कोशिशों से भरा हुआ है।

कन्हैयालाल की हत्या का जो वीडियो सामने आया था, वह किसी भी सभ्य समाज की आत्मा को झकझोरने के लिए काफी था। दो युवक रियाज अतारी और गौस मोहम्मद उसकी दुकान में ग्राहक बनकर दाखिल होते हैं और धारदार हथियार से उसका गला रेत देते हैं। न सिर्फ यह कृत्य किया गया, बल्कि उसका प्रचार भी किया गया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और घोषणा की गई कि यह हत्या "नबी के अपमान" के जवाब में की गई है। यह वही कट्टरपंथी विमर्श था जो सर तन से जुदा के नारे लगवाता है। इसके बावजूद, यह मुकदमा आज भी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है।

और इसी के समानांतर, 'उदयपुर फाइल्स' नाम की एक फिल्म जो उस

**आज सवाल सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत अब सच के सामने खड़ा हो पाने का साहस खोता जा रहा है? क्या हम सिर्फ उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जो सुविधाजनक हों? क्या अब सच्चाई अदालतों के फैसलों की मोहताज हो गई है?**

कट्टर सोच की परतें उधेड़ना चाहती है, वह अदालत के आदेश पर रुक जाती है। न्यायिक व्यवस्था की यह दोगली प्राथमिकता स्पष्ट है एक ओर खून का वीडियो सार्वजनिक है, आरोपी जेल में हैं, सबूत पुख्ता हैं, लेकिन फैसला नहीं; दूसरी ओर, एक फिल्म जो केवल सवाल उठाती है, उसे तीन दिन में प्रतिबंधित कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों की चुप्पी और भी शर्मनाक है। जो दल हर मौके पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडे लेकर सड़कों पर उतरते हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी खेमे उनकी तरफ से इस फिल्म पर न कोई प्रतिक्रिया, न कोई बयान आया। क्या इसलिए कि कन्हैयालाल हिंदू थे? या इसलिए कि यह मामला किसी विशेष वर्ग को 'असहज' कर सकता है? या इसलिए कि यह मुद्दा भाजपा के नैरेटिव को बल दे सकता है? वजह चाहे जो हो, यह चुप्पी देश के राजनीतिक विमर्श की रीढ़ तोड़ देती है।

इससे पहले 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द केरल स्टोरी' जैसी फिल्मों पर भी यही तर्क दिए गए थे कि ये समाज में तनाव फैला सकती हैं। लेकिन वे फिल्में रिलीज हुईं, दर्शकों ने देखा, प्रतिक्रिया दी, बहस हुई और देश ने

अपनी समझदारी से तय किया कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। लोकतंत्र का यही तो सौंदर्य है। लेकिन अगर हम हर असहज सच को 'सांप्रदायिक' बताकर उसका मुंह बंद करना शुरू कर दें, तो यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसा होगा। कन्हैयालाल कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, न कोई आंदोलनकारी। वे एक आम नागरिक थे जो अपनी दुकान में बैठकर रोजी-रोटी कमा रहे थे। उनकी हत्या बताती है कि अब कट्टरपंथ सिर्फ सीमाओं तक नहीं, हमारे बाजारों, दुकानों और घरों तक घुस आया है। यह चेतावनी है कि अगर इस सोच को चुनौती नहीं दी गई, तो अगला निशाना कौन होगा, यह कोई नहीं जानता।

'उदयपुर फाइल्स' को रोकना एक फिल्म का नहीं, सच्चाई का गला घोटना है। यह उन आवाजों को दबाने की साजिश है जो कट्टरपंथ से सवाल करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक बहुत ही खतरनाक मिसाल बनाता है कि अगर किसी संगठन को कोई फिल्म पसंद न आए, तो वह कोर्ट जाकर उसे रुकवा सकता है, भले ही वह फिल्म कानून के हर पैमाने पर खरी उतरती हो। आज सवाल सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत अब सच के सामने खड़ा हो पाने का साहस खोता जा रहा है? क्या हम सिर्फ उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जो सुविधाजनक हों? क्या अब सच्चाई अदालतों के फैसलों की मोहताज हो गई है? सच को कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 'उदयपुर फाइल्स' भले अभी रुकी हो, लेकिन जिस दिन वह फिर सामने आएगी, तब सवाल और तीखे होंगे, और जवाब देना और कठिन हो जाएगा। क्योंकि जब आप सच्चाई से भागते हैं, तो वो और तेजी से आपका पीछा करती है। □□

## संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में

# सहमति नहीं शक्ति से हासिल होगी स्थाई सदस्यता

अगर आपको याद हो तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष क्साबा कारोसी ने कहा था, "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थाई सदस्यता मिलनी तय है, इसलिए सवाल 'अगर' का नहीं बल्कि 'कब' का है। इसी तरह सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की 79 वीं बैठक में फ्रांस ने भारत को स्थाई सदस्य बनाने की जोरदार अपील की थी। इस बीच गत जुलाई 2025 को रियो-डी-जेनेरियो में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान महासभा के कार्य व्यवहार में सुधार लाने तथा निर्धारित लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ने के लिए भारत को सदस्यता दिए जाने के संदर्भ में भी सकारात्मक चर्चा हुई।

मालूम हो कि अमेरिका, रूस, फ्रांस के साथ ब्रिटेन भी भारत का समर्थन करता रहा है, लेकिन भारत की स्थाई सदस्यता की राह में चीन की दीवार बाधा है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता रहा है। भारत की स्पष्ट राय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढांचा 21वीं सदी की जरूरत के हिसाब से फिट नहीं है। आज दुनिया देख रही है कि संयुक्त राष्ट्र की कारगरता सिमटी जा रही है, क्योंकि वीटो प्राप्त कुछ देशों में साम्राज्यवादी मानसिकता का ज्वार आया हुआ है। यक्ष प्रश्न है कि भारत के लिए स्थाई सदस्यता हेतु वकालत तो हो रही है परंतु सदस्यता मिलना संभव कैसे हो इसका कोई हाल फिलहाल समाधान नजर नहीं आ रहा है। महासभा की वीटो प्राप्त पांच सदस्यों में से चार सदस्य समय-समय पर भारत के लिए हामी भरते रहे हैं लेकिन पांचवा सदस्य देश चीन भारत की स्थाई सदस्यता का प्रबल विरोधी है। चीन सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट वाला एकमात्र एशियाई देश है और वह कतई नहीं चाहता कि भारत को वीटो प्राप्त सदस्यता हासिल हो। क्योंकि चीन भारत के साथ प्रतिद्वंद्विता रखता है और वह नहीं चाहता की महासभा की स्थाई सदस्यता के साथ भारत की प्रतिष्ठा बढ़े।



भारत का परमाणु संपन्न राष्ट्र होना भी कई देशों को नहीं भाता। अमरीका को पिछलग्गू चाहिए, जो भारत से संभव नहीं है। रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति कायम रखी, यह अमरीका को अच्छा नहीं लगा।

— डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र



ब्रिक्स देशों का सम्मेलन बीते छह-सात जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ, जहां कई ज्वलंत मुद्दे उठे और इन्हीं में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार से संबंधित भी था। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक, प्रभावी और कुशल बनाने की वकालत की है। खास बात यह भी रही कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र में तुलनात्मक रूप से बढ़ी हुई भूमिका निभाने की ब्राजील और भारत की इच्छा का समर्थन किया है। वैसे देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मामला दशकों पुराना है। यदि अमेरिका जैसे देश वास्तव में इस मसले पर गंभीर हैं, तो सुरक्षा परिषद में बड़े सुधार को सामने लाकर भारत को स्थायी सदस्य के रूप में उसमें जगह दी जानी चाहिए। कई वर्ष पहले रूस ने जोर दिया था कि स्थायी सदस्यता के लिए भारत मजबूत दावेदार है। दुनिया के कई देश इस मामले में भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन नतीजे वहीं के वहीं हैं।

पिछले वर्ष भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा स्वरूप विश्व की बदलती जरूरतों के मुताबिक नहीं है और इसमें सुधार नितांत आवश्यक है। अब ब्रिक्स सम्मेलन में चर्चा के बाद यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने जोर दिया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार वैश्विक दक्षिण के हितों के अनुरूप होना चाहिए। यानी यह सुधार विकासशील देशों की भूमिका को विस्तार देने से भी जुड़ा होना जाना चाहिए। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर विश्व व्यापार संगठन पर भी सवाल उठते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता और उसकी सफलता तथा विफलता

की लकीर भी कमोबेश छोटी-बड़ी रही है। संदर्भ यह भी है कि किसी भी संगठन या परिषद को यदि सुधार और बदलाव से विमुख कर लंबे समय तक रखा जाए, तो उसमें गैर उपजाऊ तत्त्व स्वतः शामिल हो जाते हैं। दुनिया में भारत का बढ़ता कद मौजूदा समय में पूरी धमक के साथ प्रतिबिंबित करता है कि सुरक्षा परिषद में फेरबदल के साथ उसे स्थायी सदस्य बनाया जाए। तभी वैश्विक हित के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संतुलन संभव है।

विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शुमार था और अब तक वह सुरक्षा परिषद का आठ बार सदस्य भी रह चुका है। आखिरी बार वर्ष 2021-22 में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने अपनी भूमिका निभाई थी। मगर पूरी योग्यता और व्यापक समर्थन के बावजूद अभी तक उसे स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। हालिया परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ब्रिक्स सम्मेलन में एक बार फिर इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी है। ब्रिटेन भी सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करता रहा है, इतना ही नहीं वह भारत, जापान, ब्राजील समेत अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की बात कह चुका है। पिछले आठ दशकों से चली आ रही इस व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन की मांग अक्सर उठती रही है। दुनिया ने कई तरह के आकार और प्रकार को ग्रहण कर लिया है, मगर सुरक्षा परिषद पांच स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस के अलावा दस अस्थायी सदस्यों के साथ यथावत स्थिति में है। ऐसे में अब परिवर्तन का समय आ चुका है।

असल में सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू-राजनीतिक और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी स्थिति को देख कर की गई थी, लेकिन आठ दशकों में बहुत कुछ बदल चुका है।

देखा जाए तो शीतयुद्ध की समाप्ति के साथ ही इसमें बड़े सुधार की गुंजाइश थी, जो नहीं किया गया। पांच स्थायी सदस्यों में यूरोप का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है, जबकि आबादी के लिहाज से वह मुश्किल से पांच फीसद स्थान घेरता है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई सदस्य देश इसमें स्थायी नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का पचास फीसद कार्य इन्हीं से संबंधित है। सुरक्षा परिषद के ढांचे में सुधार इसलिए भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें अमेरिकी वर्चस्व दिखता है। भारत की सदस्यता के मामले में दावेदारी बहुत मजबूत दिखाई देती है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पीछे छोड़ कर पहला सबसे बड़ा देश बन गया है, जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का चौथा बड़ा देश है। ऐसे में भारत की दावेदारी कहीं अधिक मजबूत है। इतना ही नहीं भारत को विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और जी-20 जैसे आर्थिक संगठनों में प्रभावशाली माना जा सकता है।

एल-69 समूह जिसमें भारत, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 42 विकासशील देशों की अगुआई कर रहा है, वह भी सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता रहा है। अफ्रीकी समूह में 54 देश हैं, जो सुधारों की वकालत करते रहे हैं। इनकी मांग है कि अफ्रीका के कम-से-कम दो राष्ट्रों को 'वीटो' की शक्ति के साथ स्थायी सदस्यता दी जाए। यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है, तो चीन जैसे देशों के 'वीटो' के दुरुपयोग पर न केवल अंकुश लगेगा, — बल्कि व्याप्त असंतुलन को भी पाटा जा सकेगा। गौरतलब है कि अपनी स्थापना से अब तक सुरक्षा परिषद की सफलताओं के साथ कई नाकामियां भी जुड़ी रही हैं। यह बात सकारात्मक है कि इसके गठन के बाद तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, मगर

दुनिया कई युद्धों से गुजरी है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध जारी है। हाल में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ। इजराइल और हमास तो संघर्षरत हैं ही। इससे पहले अमेरिका के नेतृत्व में वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण, वर्ष 2008 में रूस का जार्जिया पर हमला, अरब-इजराइल युद्ध, 1994 में रवांडा का जनसंहार और 1993 में सोमालिया में गृहयुद्ध सुरक्षा परिषद की विफलता की कहानी है।

माना जाता है कि जिस स्थायी सदस्यता के लिए भारत पिछले कुछ वर्षों से प्रयासरत है, वह वर्ष 1950 के दौर में आसानी से सुलभ थी। आवश्यकता की दृष्टि से देखें, तो भारत को इसका स्थायी सदस्य इसलिए होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा परिषद प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है।

लेकिन महासभा में शामिल देश की कथनी और करनी में अंतर विरोध है। अस्थाई सदस्यता की दौड़ में भारत

आगे है लेकिन अन्य सदस्यों को यह मालूम है कि परंपरागत तौर पर भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण न केवल किसी दूसरे देश के मामलों में सीधा हस्तक्षेप आलोचना और आदेश देने से बचने का रहा है बल्कि सैद्धांतिक रूप से भी भारत किसी भी अंतर क्षेत्रीय विवाद में किसी का पक्ष लेने से परहेज करता है। भारत की गैर विस्तारवादी सोच के साथ परमाणु संपन्न होने के बावजूद 'पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति' के नैतिक आधार की भी सराहना होती है। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की दौड़ में शामिल भारत के पास न केवल तीसरी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है बल्कि हमारे अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम दुनिया में सबसे आधुनिक हैं। 2022 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म के देश के रूप में उभरा। वर्ष 2023 में भारत के पास दो शक्तिशाली वैश्विक मंचों जी20 और एसीओ की

अध्यक्षता का अनूठा विशेषाधिकार हासिल था।

दरअसल भारत का परमाणु संपन्न राष्ट्र होना भी कई देशों को नहीं भाता। अमरीका को पिछलग्गू चाहिए, जो भारत से संभव नहीं है। रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति कायम रखी, यह अमरीका को अच्छा नहीं लगा। भारत का चीन से सीमा विवाद है। वर्तमान में वीटो वाले दो देश युद्धों में उलझे हैं। ऐसे में भारत को स्थायी सदस्यता के लिए अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति मजबूत करनी ही होगी। साथ ही भारत को अपनी अंदरूनी समस्याओं जैसे असमानता गरीबी अशिक्षा मूलभूत संसाधनों की कमी बेरोजगारी आदि को भी दूर करना होगा। शक्तिशाली देश भावनाओं से नहीं व्यवहारिकता से चलते हैं। इसके लिए भारत को अपने आप को पर्याप्त मजबूत बनाना ही होगा। □□

(लेखक उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी हैं)

## :: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीऑर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि 'स्वदेशी पत्रिका' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

**सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :-**

| स्वदेशी पत्रिका | वार्षिक  | आजीवन       |
|-----------------|----------|-------------|
| हिन्दी          | 150 रुपए | 1500/- रुपए |
| अंग्रेजी        | 150 रुपए | 1500/- रुपए |

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)**

में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजें।

**स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22**

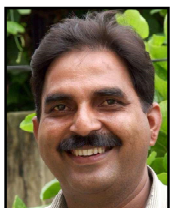
अधिक जानकारी के लिए देखें :

**http://  
swadeshionline.in/**

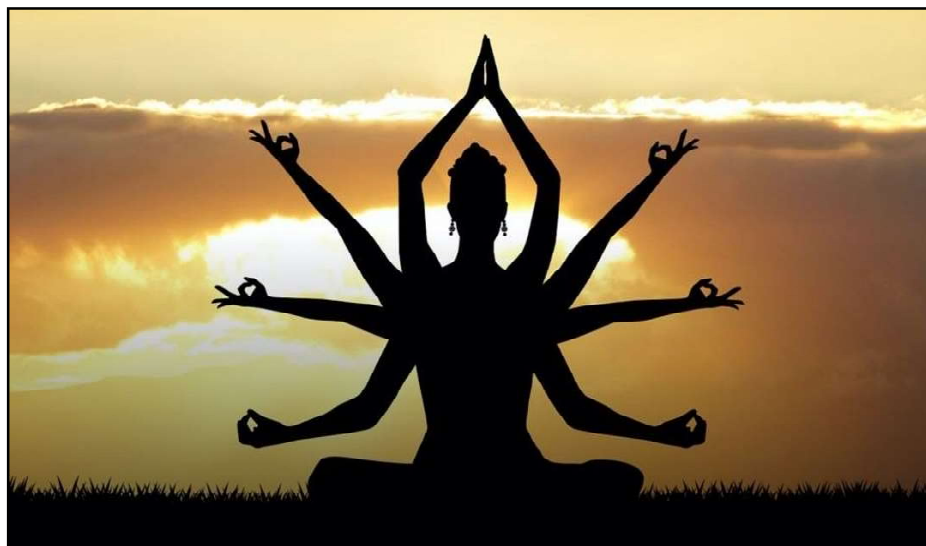
21 जून योग दिवस

# प्राचीन परंपराओं को समेटे आधुनिक युग का योगा

21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनी लोकप्रियता हासिल करता जा रहा है। 12 वर्ष पहले इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को योग दिवस मनाने का संदेश दिया था, जिसे पूरी दुनिया में सराहा और स्वीकारा गया। योग दिवस के जनक भारत में भी इस दिन योग की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ एक अनोखे उत्साह से होती है। सरकारी से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा पूरे देश में योग के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी कैबिनेट के सदस्यों से लेकर राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बुद्धिजीवी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। भाग दौड़ की इस जिदगी में शारीरिक व्यायाम जब पीछे छूटता जा रहा है ऐसे में योग दिवस शरीर को स्वस्थ रखने के लिये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन केवल शारीरिक व्यायाम का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव जीवन को संतुलित करने की एक गहरी कला का उत्सव है। बीते वर्ष 21 जून की सुबह की ठंडी हवा में, जब दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोग योग के लिए एकत्र हुए, तो वह दृश्य किसी सांस्कृतिक उत्सव से कम नहीं था। रंग-बिरंगे योग मैट, अलग-अलग उम्र के लोग, और एक सामूहिक ऊर्जा ने वातावरण को जीवंत कर दिया। यह केवल एक दिन की बात नहीं थी; यह एक वैश्विक आंदोलन का हिस्सा था, जो भारत की प्राचीन परंपरा को दुनिया के कोने-कोने तक ले गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है।



यह दिन हमें याद दिलाता है कि योग केवल एक प्राचीन परंपरा नहीं, बल्कि एक आधुनिक समाधान है, जो हमें एक स्वस्थ, संतुलित, और सार्थक जीवन की ओर ले जाता है।  
— संजय सक्सेना



योग, जो कभी भारतीय ऋषि-मुनियों की तपस्या का हिस्सा था, आज एक वैज्ञानिक और समग्र जीवन शैली के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, फिर भी यह आधुनिक जीवन की जटिलताओं के लिए उतना ही प्रासंगिक है। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव जब भारत ने 2014 में रखा, तो इसे 177 देशों का समर्थन मिला। यह केवल एक राजनयिक जीत नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक

एक तरफ जहां युवा सूर्य नमस्कार के गतिशील आसनो में ऊर्जा पाते हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक प्राणायाम और ध्यान में शांति तलाशते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उम्र, लिंग, या सामाजिक स्थिति की सीमाओं को तोड़ती है, लेकिन योग दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है; यह एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है। आधुनिक जीवनशैली में तनाव, चिंता, और शारीरिक रोगों की बढ़ती संख्या ने योग को और भी जरूरी बना दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं 2030 तक

हैं। पतंजलि के योगसूत्र, जो योग के आठ अंगों—कृयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधिकृका—वर्णन करते हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। फिर भी, बाजारीकरण और व्यावसायीकरण ने योग को कभी-कभी एक फैशन स्टेटमेंट या फिटनेस ट्रेंड तक सीमित कर दिया है। योग स्टूडियो, महंगे योग मैट, और डिज़ाइनर योग वस्त्र इसकी मूल सादगी को चुनौती देते हैं।

इसके बावजूद, 21 जून का दिन हमें याद दिलाता रहता है कि योग



**२१ जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव जब भारत ने २०१४ में रखा, तो इसे १७७ देशों का समर्थन मिला। यह केवल एक राजनयिक जीत नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक साझा दृष्टिकोण था। योग का अर्थ केवल आसन या शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है; यह मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कला है।**

साझा दृष्टिकोण था। योग का अर्थ केवल आसन या शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है; यह मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कला है।

इस दिन दिल्ली के अलावा देश के कोने-कोने में और दुनिया के विभिन्न शहरों में लोग योग के लिए एकत्र होते हैं। स्कूलों में बच्चे, कार्यालयों में कर्मचारी, और गांवों में किसान, सभी ने अपने-अपने तरीके से इस दिन को मनाते हैं। गौरतलब हो, योग की यह सार्वभौमिक स्वीकार्यता इसके लचीलेपन और समावेशी स्वभाव को दर्शाती है।

वैश्विक स्वास्थ्य बोझ का एक बड़ा हिस्सा होंगी। योग, विशेष रूप से ध्यान और प्राणायाम, तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्रभावी साबित हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि नियमित योग अभ्यास से कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, जिससे चिंता और अवसाद में कमी आती है।

हालांकि, योग के प्रचार में कुछ चुनौतियां भी हैं। इसे केवल एक शारीरिक व्यायाम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति ने इसके आध्यात्मिक और दार्शनिक आयामों को धुंधला किया

केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी है। योग हमें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रेरणा देता है। जब लोग एक साथ योग करते हैं, तो एक सामूहिक ऊर्जा पैदा होती है, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव लाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि योग केवल एक प्राचीन परंपरा नहीं, बल्कि एक आधुनिक समाधान है, जो हमें एक स्वस्थ, संतुलित, और सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। □□

# अमेरिका पर ही भारी पड़ सकता है टैरिफ युद्ध

अमेरिका में डानल्ड ट्रम्प के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही दुनिया के लगभग समस्त देशों के साथ ट्रम्प प्रशासन द्वारा टैरिफ युद्ध की घोषणा कर दी गई। अमेरिका में विभिन्न देशों से होने वाले आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर एवं टैरिफ की दरों में बार बार परिवर्तन कर तथा इन टैरिफ की दरों को लागू करने की तिथि में परिवर्तन कर ट्रम्प प्रशासन टैरिफ युद्ध को किस दिशा में ले जाना चाह रहा है, इस सम्बंध में अब स्पष्टता का पूर्णतः अभाव दिखाई देने लगा है। अब तो विभिन्न देशों को ऐसा आभास होने लगा है कि अमेरिकी प्रशासन विभिन्न देशों पर टैरिफ की दरों के माध्यम से अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि ये देश अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अमेरिकी शर्तों पर शीघ्रता के साथ सम्पन्न करें।

ट्रम्प द्वारा कई बार यह घोषणा की गई है कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता शीघ्र ही सम्पन्न किया जा रहा है। अमेरिका एवं भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधि मंडल अमेरिका में गया था तथा निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक वहां रहा एवं ऐसा कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय समझौते के अंतिम रूप को अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है परंतु अभी तक अमेरिका द्वारा अमेरिका एवं भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा नहीं की जा रही है। हालांकि, इस बीच अमेरिका द्वारा कई देशों के विरुद्ध टैरिफ की दरों को बढ़ा दिया गया है। विशेष रूप से जापान एवं दक्षिणी कोरिया से अमेरिका को आयात होने वाली वस्तुओं पर 1 अगस्त 2025 से 25 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाया जाएगा। इसी प्रकार, 12 अन्य देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर भी टैरिफ की बढ़ी हुई नई दरें लागू किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन 14 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पत्र भी लिखा है। इस सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है।



अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों में तो डॉक्टर एवं इंजीनियरों की भारी मांग पूर्व से ही बनी हुई है। अतः आज भारत पूरे विश्व में डॉक्टर, इंजीनियर तथा श्रमिक उपलब्ध कराने के मामले बहुत आगे है।  
— प्रहलाद सबनानी

पूर्व में अमेरिका द्वारा चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ की घोषणा की गई थी। चीन ने भी अमेरिका से होने वाली आयातित वस्तुओं पर लगभग उसी दर पर टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी थी। साथ ही, चीन ने विभिन्न देशों को दुर्लभ खनिज पदार्थों (रेयर अर्थ मिनरल) के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अमेरिका में चीन के इस निर्णय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जिसके दबाव में अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार समझौता करते हुए चीन से आयात होने वाली विभिन्न वस्तुओं पर टैरिफ की दरों को तुरंत कम कर दिया। अमेरिका द्वारा इसी प्रकार का एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता ब्रिटेन के साथ भी सम्पन्न किया जा चुका है। पूर्व में, ट्रम्प प्रशासन ने 90 दिवस की अवधि में 90 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने की बात कही थी तथा 90 दिवस की समयावधि 9 जुलाई को समाप्त होने के पश्चात भी केवल दो देशों ब्रिटेन एवं चीन के साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता सम्पन्न हो सका है। भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा चुका है परंतु इसकी अभी तक घोषणा नहीं की गई है। द्विपक्षीय समझौते के लिए शेष देशों पर दबाव बनाने की दृष्टि से ही इन देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर टैरिफ की दरों को एक बार पुनः बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है और इन बढ़ी हुई दरों को 1 अगस्त 2025 से लागू करने की योजना बनाई गई है।

वैश्विक स्तर पर अमेरिका द्वारा छेड़े गए इस टैरिफ युद्ध से निपटने के लिए भारत एक विशेष रणनीति के अंतर्गत कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने वैश्विक मंच पर न तो अमेरिका के टैरिफ की दरों में वृद्धि सम्बंधी निर्णयों की आलोचना की है और न ही भारत में अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। बल्कि, भारत ने तो अमेरिका से आयात होने वाली कुछ विशेष वस्तुओं पर टैरिफ को कम कर दिया है। दरअसल, भारत इस समय विकास के उस चक्र में पहुंच गया है जहां पर भारत को अपना पूरा ध्यान आर्थिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत को यदि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करना है तो आगे आने वाले लगभग 20 वर्षों तक लगातार लगभग 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर को बनाए रखना अति आवश्यक है। इसलिए भारत एक विशेष रणनीति के अंतर्गत अपने आर्थिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के रूस के साथ भी अच्छे सम्बंध हैं तो अमेरिका से भी अपने सम्बंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे सम्बंध हैं तो ईरान के साथ भी भारत के व्यापारिक सम्बंध हैं। रूस एवं यूक्रेन युद्ध के बीच भी भारत ने दोनों देशों के साथ अपना संतुलित व्यवहार बनाए रखा है। इसी कड़ी में, चीन के साथ भी आवश्यकता अनुसार बातचीत का दौर जारी रखा जा रहा है, बावजूद इसके कि कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विरुद्ध कार्य करता हुआ दिखाई देता है।

अभी हाल ही में चीन ने भारत को दुर्लभ खनिज पदार्थों (रेयर अर्थ मिनरल) की आपूर्ति पूर्णतः रोक दी है। साथ ही, मानसून का मौसम भारत में प्रारम्भ हो

चुका है एवं भारत में कृषि क्षेत्र में गतिविधियां अपने चरम स्तर पर पहुंच गई हैं, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण समय पर चीन द्वारा भारत को उर्वरकों की आपूर्ति पर परेशनियां खड़ी की जा रही हैं। चीन द्वारा समय समय पर भारत के लिए खड़ी की जा रही विभिन्न समस्याओं के हल हेतु भारत ने विश्व के पूर्वी देशों एवं विश्व के दक्षिणी भाग में स्थित देशों की ओर रुख किया है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घाना, नामीबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, त्रिनिदाद एवं टोबैगो जैसे देशों की यात्रा इस उद्देश्य से सम्पन्न की है ताकि दुर्लभ खनिज पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इन देशों में दुर्लभ खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

भारत में 140 करोड़ नागरिकों का विशाल बाजार उपलब्ध है, जिसे अमेरिका एवं चीन सहित विश्व का कोई भी देश नजर अन्दाज नहीं कर सकता है। यदि अमेरिका एवं चीन भारत के साथ अपने सम्बंधों को किसी भी कारण से बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो लम्बी अवधि में इसका नुकसान इन्हीं देशों को अधिक होने जा रहा है क्योंकि ऐसी स्थिति में वे भारत के विशाल बाजार से वंचित हो जाने वाले हैं। भारत तो वैसे भी पिछले लम्बे समय से आत्मनिर्भर होने का लगातार प्रयास कर रहा है एवं कई क्षेत्रों में भारत आज आत्मनिर्भर बन भी गया है। अतः भारत की निर्भरता अन्य देशों पर अब कम ही होती जा रही है। भारत आज फार्मा, ऑटो, कृषि, इंजीनियरिंग, टेक्नॉलोजी, स्पेस तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि क्षेत्रों में बहुत आगे निकल चुका है। आज भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसकी अनदेखी विश्व का कोई भी देश नहीं कर सकता है। भारत को हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कच्चे तेल के अपार भंडार होने का भी पता लगा है। एक अनुमान

के अनुसार, यह भंडार इतने विशाल हैं कि आगामी 70 वर्षों तक भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति होती रहेगी। इसी प्रकार, भारत में कर्नाटक स्थित कोलार स्वर्ण खदानों में भी एक बार पुनः खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। आरम्भिक अनुमान के अनुसार, प्रतिवर्ष लगभग 750 किलोग्राम स्वर्ण की आपूर्ति भारत को इन खदानों से हो सकती है।

पूरे विश्व में आज केवल भारत ही युवा देश की श्रेणी में गिना जा रहा है क्योंकि भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयुवर्ग में हैं तथा लगभग 40 प्रतिशत आबादी 15 से 35 वर्ष के आयुवर्ग में शामिल हैं। अतः एक तरह से भारत आज विश्व के लिए श्रम का आपूर्ति केंद्र बन गया है। लम्बे समय से रूस एवं यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद जब इन देशों में आधारभूत सुविधाओं को पुनर्विकसित करने का कार्य प्रारम्भ होगा तो इन्हें भारतीय श्रमिकों एवं इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ने जा रही है, एक अनुमान के अनुसार अकेले रूस द्वारा में लगभग 10 लाख भारतीयों की मांग की जा सकती है।

इसी प्रकार, इजराइल एवं हम्मस तथा ईरान के बीच युद्ध की समाप्ति के पश्चात इन देशों में भी बुनियादी ढांचे को पुनः मजबूत करने का कार्य जब प्रारम्भ होगा तो इन देशों को भी भारतीय नागरिकों की आवश्यकता पड़ेगी। इजराइल, जापान सिंगापुर एवं ताईवान आदि देशों द्वारा तो पूर्व में भी भारतीय इंजीनियरों की मांग की जाती रही है। अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों में तो डॉक्टर एवं इंजीनियरों की भारी मांग पूर्व से ही बनी हुई है। अतः आज भारत पूरे विश्व में डॉक्टर, इंजीनियर तथा श्रमिक उपलब्ध कराने के मामले बहुत आगे है। अतः भारत की इस ताकत की अनदेखी आज कोई भी देश नहीं कर सकता है। □□

# भारत की ग्रामीण क्रांति ने वैश्विक विकास को कैसे परिभाषित किया

कुछ आँकड़े आपको रोकते हैं, कुछ चौंकाते हैं, कुछ उपलब्धियों को दर्शाते हैं। आंकड़े कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बताते हैं — बल्कि वे एक राष्ट्र की कथा को बदलते हैं। ऐसा ही एक आंकड़ा है गरीबी दर में गिरावट का, जो उत्साहित करता है। एक आंकड़े के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1 प्रतिशत से गिरकर 2022-23 में सिर्फ 5.3 प्रतिशत रह गई है। इसका मतलब है कि 269 मिलियन भारतीय — लगभग एक पूरे महाद्वीप की आबादी — केवल एक दशक में अत्यधिक गरीबी के चंगुल से मुक्त हो गए हैं। इस चौंका देने वाले आंकड़े के पीछे न केवल सौभाग्य या आर्थिक विकास है, बल्कि प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में एक शांत क्रांति है। ग्यारह साल का दृढ़, जमीनी स्तर का शासन, कड़ी मेहनत से सुधार, और भारत की सबसे उपेक्षित ताकत का पुनरुद्धार — इसका सहकारी आर्थिक ढांचा।

यह सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है; यह मानसिकता, मशीनरी और विकास के अर्थ का परिवर्तन है। बहुत लंबे समय तक, गरीबी उन्मूलन को चैरिटी या टॉप-डाउन कल्याण के रूप में देखा गया। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में, गरीबी में कमी सशक्तिकरण का परिणाम बन गई है, पात्रता नहीं। और इस परिवर्तन का धड़कता दिल?

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट इस बदलाव को वैश्विक मान्यता देती है, लेकिन भारतीय इसे रोजाना जी रहे हैं। यह स्वीकार करता है कि हम जमीन पर पहले से ही क्या जानते थे: यह केवल सांख्यिकीय भाग्य नहीं है। यह जानबूझकर संरचनात्मक सुधारों, संस्थागत नवाचारों और अंतिम मील में समृद्धि लाने के लिए एक अथक परिश्रम का परिणाम है। पहली बार, विश्व बैंक को गरीबी को मापने और निपटने के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जाता है — विदेशी सहायता या राजकोषीय सॉच के साथ नहीं, बल्कि किसान



भारत ने साबित कर दिया है कि गरीबी निर्भरता से पराजित नहीं होती है — इसे गरिमा द्वारा कुचल दिया जाता है।  
— विजय गर्ग



केंद्रित प्रणालियों, ग्रामीण संस्थानों और स्थानीय धन सृजन के माध्यम से।

सबसे महत्वपूर्ण गरीबी में कमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में हुई है। ये वो राज्य हैं जो ग्रामीण और कृषि के रूप में वे आबादी के रूप में कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है। ये वही राज्य भी हैं जहां सहकारी आंदोलनों ने पिछले एक दशक में गहरी जड़ पकड़ ली है, जहां पैक्स का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जहां एफपीओ संपन्न हो रहे हैं, और जहां ग्रामीण महिलाएं गर्व के साथ डेयरी और बीज सहकारी समितियों का नेतृत्व करती हैं। पिछले ग्यारह वर्षों में, पीएम मोदी ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं — उन्होंने शासन में सुधार किया है। मंत्रालय मिशन—उन्मुख हो गए हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना बाद में नहीं, बल्कि एक घोषणा के रूप में की गई थी कि भारत के गाँव मायने रखते हैं। सहकारी समितियाँ अब हाशिए पर नहीं हैं — वे हमारी आर्थिक योजना के लिए केंद्रीय हैं। निर्यात, बीज और जैविक उपज के लिए तीन नए राष्ट्रीय स्तर के बहुस्तरीय सहकारी संस्थानों के निर्माण के साथ, संदेश जोर से और स्पष्ट है: भारत अपने जमीनी स्तर से उठेगा।

और यह अब एक भावनात्मक या सांस्कृतिक विश्वास नहीं है — यह एक आर्थिक वास्तविकता है। खरीद योजना अब उत्पादन के साथ एकीकृत है। किसान अब अंधेरे में नहीं बढ़ रहे हैं। वे पहले से जानते हैं कि कौन उनकी उपज खरीदेगा, किस कीमत पर, और कब। इस प्री-सीजन निश्चितता ने खेल को बदल दिया है। इसमें ग्रामीण वेयरहाउसिंग क्रांति जोड़ें, जहां पैक्स को सेवा और भंडारण केंद्रों में अपग्रेड किया जा रहा है, और आपके पास एक प्रणाली है जहां मूल्य लीक नहीं होता है — यह किसान के साथ रहता है।

यह परिवर्तन केवल एक भारतीय

**सबसे महत्वपूर्ण गरीबी में  
कमी उत्तर प्रदेश,  
महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम  
बंगाल और मध्य प्रदेश  
में हुई है। ये वो राज्य हैं  
जो ग्रामीण और कृषि के  
रूप में वे आबादी के  
रूप में कर रहे हैं।**

सफलता की कहानी नहीं है — यह एक ऐसा मॉडल है जो वैश्विक विकास सोच की नींव को चुनौती देता है। वर्षों से, विश्व बैंक, आईबीआरडी और विभिन्न जलवायु वित्त निकायों जैसी संस्थाओं ने अरबों डॉलर की शहरी परियोजनाओं के साथ विकास को समान किया है, जो अक्सर ग्रामीण वास्तविकताओं से अलग हो जाते हैं। हालांकि, भारत ने दिखाया है कि संरचनात्मक गरीबी में कमी, आर्थिक गरिमा और जलवायु लचीलापन सहयोग के नेतृत्व वाले शासन में निहित होने पर हाथ से जा सकते हैं।

कृषि में निवेश — विशेष रूप से खरीद बुनियादी ढांचे में — किसान के आसपास भारत की आपूर्ति श्रृंखला को फिर से उन्मुख किया है। यह अब व्यथित बिक्री और बिचौलियों की प्रणाली नहीं है। यह स्थानीय संस्थानों द्वारा आगे की योजना बनाई गई खरीद, भंडारण और वितरण का एक मॉडल है। आपूर्ति श्रृंखला में यह सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली व्यवधान पहले ही शुरू हो चुका है कि विकास को कैसे वित्तपोषित, मापा और वितरित किया जाता है। वेयरहाउसिंग फसल के बाद के नुकसान को कम करता है — यह जलवायु कार्रवाई है। स्थानीय खरीद उत्सर्जन और परिवहन लागत पर कटौती करती है — यह शमन है। सामुदायिक सिंचाई पानी

बचाती है — यह अनुकूलन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये विकास के मॉडल हैं जो स्वयं लोगों के स्वामित्व, रन और निरंतर हैं। यही कारण है कि 5 जुलाई से शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र में आगामी उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच को रोकना और प्रतिबिंबित करना चाहिए। एसडीजी प्लेबुक अब भारत की सहकारी नेतृत्व वाली सफलता को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि दुनिया एसडीजी 1 (नो पॉवर्टी), एसडीजी 2 (जीरो हंगर), एसडीजी 13 (क्लाइमेट एक्शन) और एसडीजी 8 (डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ) को प्राप्त करने के बारे में गंभीर है। उस स्थिति में, इसे पुराने सहायता प्रतिमानों से परे देखना चाहिए। इसे भारत की ओर देखना चाहिए। भारत ने साबित कर दिया है कि गरीबी निर्भरता से पराजित नहीं होती है — इसे गरिमा द्वारा कुचल दिया जाता है। जब किसानों को लाभार्थियों के रूप में नहीं बल्कि उद्यमियों के रूप में देखा जाता है, जब आपूर्ति श्रृंखला उत्पादकों के चारों ओर घूमती है, और जब समुदाय अपना लचीलापन बनाते हैं, तो परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहानी का अंत नहीं है — यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक अध्याय जहां दुनिया अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करती है, जहां वित्तीय संस्थान जमीनी ज्ञान के साथ संरेखित होते हैं, और जहां ग्रामीण भारत आगे का रास्ता दिखाता है। आइए हम भारत से दुनिया को एक संदेश भेजें: गरीबी भाग्य नहीं है। समृद्धि कोई विशेषाधिकार नहीं है। सही संरचना, भावना और समर्थन के साथ, कोई भी राष्ट्र उठ सकता है। लेकिन ऐसा होने के लिए, दुनिया को अंततः भारत की आवाज सुननी चाहिए — अपने गांवों, उसके सहकारी समितियों और उसके लोगों से। □□

*विजय गर्ग (सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद, गली कौर चंद एमएचआर मल्लो पंजाब)*

## ब्रांडेड बनाम जेनेरिक

## दवा के बाजार में दर्द का व्यापार

भारत में स्वास्थ्य सेवा ऐसा क्षेत्र है, जहां लाखों लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दवाओं पर निर्भर हैं, लेकिन दवाओं के बाजार में एक बड़ा सवाल हमेशा चर्चा में रहता है कि उपभोक्ता द्वारा खरीदी जा रही दवाई सही है या नहीं। एक बड़ा मसला ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं को लेकर भी है। कुछ चिकित्सक जेनेरिक दवाओं के बारे में मरीज को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश चिकित्सक अभी भी ब्रांडेड दवाओं को ही प्रमुखता दे रहे हैं। दवा के बाजार में जेनेरिक और ब्रांडेड का ऐसा घालमेल हुआ है की आम उपभोक्ता शारीरिक नुकसान के साथ-साथ आर्थिक हानि उठाने के लिए भी मजबूर हो जाता है।

अभी हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी है कि दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए पिछले तीन वर्षों में देश भर में दवाओं के तीन लाख से ज्यादा नमूने जांच के लिए एकत्रित किए गए, जिनमें से 9000 से अधिक दवाएं गुणवत्ता के आधार पर घटिया पाई गईं। इनमें से 951 दवाएं या तो नकली थी या मिलावटी थी। इनमें सबसे ज्यादा 3104 दवाएं साल 2024-25 में मानकों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2022 से देश भर में दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों की जोखिम के आधार पर निरीक्षण प्रणाली शुरू की गई है। अब तक 905 दवा निर्माण इकाइयों की जांच की गई जिनमें से 694 मामले में कंपनियों के विरुद्ध उत्पादन रोकने, लाइसेंस रद्द करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने आदि जैसी प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है।

उल्लेखनीय है कि जब भी उपभोक्ता दवा खरीदने के लिए दवा की दुकान पर जाता है तो उसके दिमाग में पहली बात यही आती है कि ब्रांडेड या जेनेरिक दवाएं? ऐसे में सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। यह जानना भी जरूरी है कि कैसे फार्मास्युटिकल कंपनियां भोले-भाले ग्राहकों का शोषण कर रही हैं। यह ऐसा विषय है जिसने दर्द के व्यापार को बढ़ावा दिया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रांडेड या



भारत जैसे देश, जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही कई लोगों के लिए सुलभ नहीं हैं, ऐसे में जेनेरिक दवाएं वरदान हैं।

— शिवनंदन लाल



जेनेरिक दवाएं क्या हैं?

ब्रांडेड दवाएं वे होती हैं, जो किसी फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा अपने ब्रांड नाम के तहत बेची जाती हैं। ये दवाएं आम तौर पर महंगी होती हैं क्योंकि इनमें कंपनी की ब्रांड वैल्यू, मार्केटिंग लागत और अनुसंधान एवं विकास का खर्च शामिल होता है। दूसरी ओर, जेनेरिक दवाएं वही दवाएं होती हैं, जिनमें वही सक्रिय रासायनिक तत्व एपीआर (एक्टिव फार्मास्युटिक इंग्रेडिएंट) होते हैं, जो ब्रांडेड दवाओं में होते हैं, लेकिन इन्हें किसी ब्रांड नाम के तहत नहीं बेचा जाता। जेनेरिक दवाएं आम तौर पर सस्ती होती हैं क्योंकि इनमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग का खर्च नहीं होता। जैसे क्रोसिन का जेनेरिक विकल्प पैरासिटामोल है, जो उसी तरह काम करता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम होती है।

भारत जैसे देश, जहां अधिकांश आबादी मध्यम और निम्न-आय वर्ग से आती है, में जेनेरिक दवाओं का महत्व अधिक है। भारत सरकार ने जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए 'जन औषधि योजना' शुरू की है। इसके तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90 प्रतिशत तक सस्ती मिलती हैं। जैसे टेल्मिसार्टन, जो उच्च रक्तचाप के लिए उपयोग की जाती है, इसकी 10 गोलियों की कीमत 200-300 रुपये हो सकती है। वहीं, टेल्मिसार्टन की जेनेरिक दवा की कीमत 20-50 रुपये हो सकती है। यह अंतर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।

जानकारों के मुताबिक फार्मास्युटिकल कंपनियों की लूट का सबसे बड़ा कारण उनकी मार्केटिंग रणनीति और ब्रांडिंग है। ये कंपनियां ब्रांडेड दवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करती हैं।

**भारत सरकार ने जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने, जागरूकता अभियान चलाने और डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।**

डॉक्टरों को मुफ्त नमूने, विदेश यात्राएं और अन्य प्रलोभन दिए जाते हैं ताकि वे मरीजों को ब्रांडेड दवाएं लिखें। नतीजा यह होता है कि मरीज, जो ज्यादातर दवाओं की तकनीकी जानकारी से अनजान होते हैं, महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई फार्मा कंपनियां एक ही दवा को अलग-अलग ब्रांड नाम से भी बेचती हैं, जिससे बाजार में भ्रम पैदा होता है। जैसे पैरासिटामोल को विभिन्न कंपनियों क्रोसिन, कालपोल व डोलो आदि नामों से बेचती हैं। लेकिन इन सभी में एक ही सक्रिय तत्व होता है। मरीजों को लगता है कि ब्रांडेड दवा ज्यादा प्रभावी होगी जबकि हकीकत में जेनेरिक दवा भी उतनी ही प्रभावी होती है। भारत में जेनेरिक दवाओं के प्रति कई मिथक प्रचलित हैं। जो फार्मा कंपनियों द्वारा फैलाए गए हैं। आम धारणा है कि जेनेरिक दवाएं कम गुणवत्ता वाली होती हैं। यह गलत है। भारत में जेनेरिक दवाओं का निर्माण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत सख्त नियमों के अधीन होता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सुनिश्चित करता है कि जेनेरिक दवाएं गुणवत्ता और प्रभावशीलता में ब्रांडेड दवाओं के बराबर हों। हालांकि, कुछ छोटी दवा कंपनियां, जो जेनेरिक दवाएं बनाती हैं, गुणवत्ता

नियंत्रण में कमी कर सकती हैं। लेकिन यह समस्या जेनेरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, कुछ ब्रांडेड दवाओं में भी गुणवत्ता की कमी देखी गई है। इसलिए मरीजों को विश्वसनीय जन औषधि केंद्रों या लाइसेंसप्राप्त फार्मसी से ही दवाएं खरीदने की राय दी जाती है।

भारत सरकार ने जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने, जागरूकता अभियान चलाने और डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मरीजों को डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवा का विकल्प हो सकती है। फार्मा कंपनियों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ अनैतिक है। सरकार को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो फार्मा कंपनियों को जेनेरिक दवाओं के उत्पादन-वितरण में प्रोत्साहित करें। दवाओं की कीमतों पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए ताकि मरीजों को उचित मूल्य पर दवाएं मिल सकें। भारत जैसे देश, जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही कई लोगों के लिए सुलभ नहीं हैं, ऐसे में जेनेरिक दवाएं वरदान हैं। लेकिन फार्मा कंपनियों के लालच और भ्रामक मार्केटिंग के कारण मरीजों को अनावश्यक रूप से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। यह समय है कि हम जागरूक हों, जेनेरिक दवाओं को अपनाएं और सरकार से मांग करें कि दवा बाजार में पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करे। जागरूकता और सही नीतियों से ही हम इस लूट को रोक सकते हैं, और हर भारतीय को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकते हैं। □□

(लेखक आकाशवाणी दिल्ली के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हैं)

# रिपोर्ट के आईने में भारत की विकास गाथा

भारत की विकास यात्रा को अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वर्णित किया जाता है यथा – सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत बना तकनीकी महाशक्ति, आदि आदि। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आँकड़ों से परे, इसकी प्रगति का वास्तविक मापदंड यह है कि विकास कितनी समानता के साथ हो रहा है। अर्थव्यवस्था का लाभ समाज के हर वर्ग को मानक के अनुसार प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।

हाल ही में आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट, पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ़ (अप्रैल 2025) के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि के साथ गरीबी में समावेशी रूप से कमी आई है। लेकिन जैसा कि अक्सर व्यापक आर्थिक आँकड़ों के साथ फेरबदल होता है, और यह सवाल उठता है कि क्या ये सुधार वास्तव में ज़मीनी हकीकत हैं, या सिर्फ़ कागज़ी आँकड़ों का भ्रम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रस्तुत आँकड़े हाथी के दांत सरीखे हैं, जो फलितार्थ में खाने के और तथा दिखाने के और हैं। क्योंकि हमारे देश में सांख्यिकी आँकड़ों को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष के बीच कितना हकीकत कितना फसाना की जोर आजमाईश आम है।

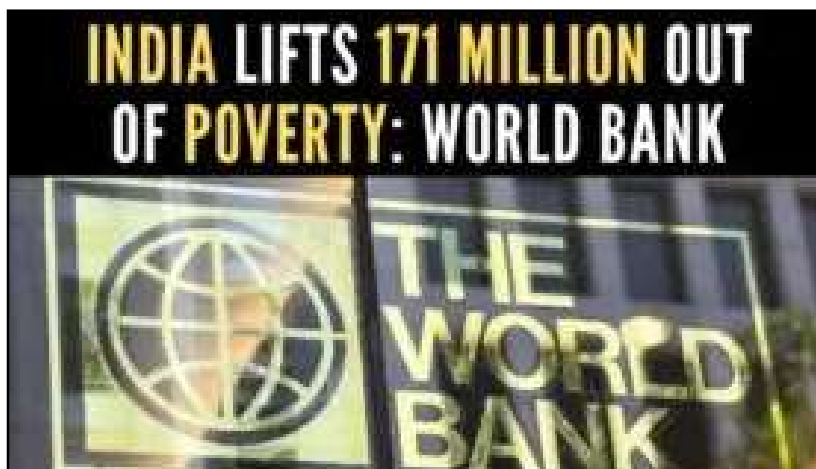
लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या भारत में गरीबी में कमी महज सांख्यिकीय तथ्य मात्र है? विश्व बैंक की ओर से प्रस्तुत यह मुख्य और ताजा आँकड़ा किसी भी मानक से देखा जाए, तो असाधारण है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार, अत्यंत गरीबी – यानी प्रतिदिन 2.15 डालर (2017 की क्रय शक्ति समता के अनुसार) से कम पर जीवन यापन – 2011-12 में 16.2 प्रतिशत थी जो घटकर 2022-23 में मात्र 2.3 प्रतिशत रह गई है। इस बदलाव ने लगभग 17.1 करोड़ लोगों को सबसे गंभीर अभाव की स्थिति से बाहर निकाला है।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच की खाई का कम होना: ग्रामीण क्षेत्र की अत्यंत गरीबी 18.4 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई है, जबकि शहरी गरीबी 10.7 प्रतिशत से घटकर केवल 1.1 प्रतिशत रह गई है। पहले जो अंतर 7.7 प्रतिशत अंकों का था, वह अब घटकर केवल 1.7 प्रतिशत का रह गया है। यह न केवल व्यापकता को दर्शाता है, बल्कि भौगोलिक समावेशन को भी दिखाता है। साथ ही, भारत ने बहुआयामी गरीबी से निपटने में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-06 में 53.8 प्रतिशत थी, जो 2019-21 में घटकर 16.4 प्रतिशत हो गई, और 2022-23 में यह और घटकर 15.5 प्रतिशत पर आ गई। इसका मतलब है कि अब अधिक भारतीय परिवारों को बिजली, बेहतर स्वच्छता और बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हैं। यह समावेशिता भारत के पांच सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों – उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश – में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन पांच राज्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत गरीबी में आई कमी में दो-तिहाई का योगदान दिया है।

हालांकि, कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि भारत में गरीबी की दर में आई गिरावट वास्तविक नहीं है, बल्कि यह सिर्फ़ इसलिए बेहतर दिखती है क्योंकि विश्व बैंक अभी भी पुरानी गरीबी रेखाओं और पुरानी मुद्रा मूल्यों का उपयोग कर रहा है। उनका कहना है कि अगर नए वैश्विक मानकों – जैसे कि 2021 की कीमतों पर आधारित 3.00 डालर प्रतिदिन



हाल ही में आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट, पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ़ के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि के साथ गरीबी में समावेशी रूप से कमी आई है।  
—अन्नू कुमारी



— का उपयोग किया जाए, तो भारत में गरीबी दर फिर से बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर, इस नई रेखा के अनुसार 2022–23 में भारत की अत्यंत गरीबी दर 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो जाएगी। लेकिन यह दृष्टिकोण एक अहम बात को नज़रअंदाज़ करता है: गरीबी सिर्फ आय की बात नहीं है। भारत ने बहुआयामी गरीबी को घटाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो जीवन की वास्तविक स्थितियों — जैसे बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, और शिक्षा की उपलब्धता — को मापती है। इन बातों को धरेलू सर्वेक्षणों के माध्यम से सीधे मापा जाता है और ये वैश्विक मूल्य परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होते। 2005–06 से लेकर 2022–23 तक भारत की बहुआयामी गरीबी 53.8 प्रतिशत से घटकर मात्र 15.5 प्रतिशत रह गई है। इसलिए इस स्तर की प्रगति को केवल तकनीकी गरीबी रेखा में बदलाव के आधार पर नकारा नहीं जा सकता।

तो यदि आय आधारित गरीबी में गिरावट महज़ एक आँकड़ों का खेल थी, तो हम लोगों के दैनिक जीवन में हुए वास्तविक सुधार को कैसे समझाएँ?

**कम होते फासले : आय से परे की प्रगति**

असमानता के दृष्टिकोण से, इसी अवधि में उपभोग—आधारित गिनी

सूचकांक 28.8 से घटकर 25.5 हो गया, जो अधिक न्यायसंगत उपभोग की ओर एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। जबकि वैकल्पिक स्रोत, जैसे कि विश्व असमानता डेटाबेस, सुझाव देता हैं कि आय असमानता बढ़ी है — 2023 में 62 के गिनी गुणांक का हवाला देते हुए — उपभोग असमानता में गिरावट अभी भी इंगित करती है कि, कम से कम जीवन स्तर के संदर्भ में, असमानताएं कम हुई हैं। किस बात ने इस परिवर्तन को संभव बनाया? लक्षित सार्वजनिक नीति, आर्थिक विस्तार और रोजगार पैटर्न में संरचनात्मक बदलावों का अभिसरण। नीति के मोर्चे पर, स्वच्छ भारत (स्वच्छता), सौभाग्य (बिजली), उज्ज्वला योजना (स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन), पीएमएवाई (आवास), और पीएम—किसान (किसानों के लिए आय सहायता) जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों ने शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में बुनियादी जीवन स्थितियों में काफी सुधार किया है जबकि आधार—आधारित पहचान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ने पारदर्शी कल्याण प्रणाली बनाने में मदद की है।

**विकास की ओर अग्रसर भारत का विकसित होता श्रम बाजार**

आर्थिक मोर्चे पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021–22 की अवधि के बाद से रोजगार वृद्धि ने कामकाजी

आयु वर्ग की आबादी को पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 24–25 की पहली तिमाही में शहरी बेरोजगारी घटकर 6.6 प्रतिशत रह गई, जो 2017–18 के बाद सबसे कम है। स्वरोजगार में तेजी आई है, खासकर ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच। 2018–19 की अवधि के बाद पहली बार, अधिक पुरुष श्रमिक ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं, जबकि कृषि में महिला रोजगार बढ़ रहा है। यह एक गतिशील श्रम बाजार को दर्शाता है जो महिलाओं और ग्रामीण कार्यबल को तेजी से शामिल कर रहा है। हालांकि, युवा बेरोजगारी 13.3 प्रतिशत और तृतीयक शिक्षा स्नातकों में 29 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है। यह भारत के शिक्षित युवाओं की रोजगार क्षमता पर सवाल उठाता है। औपचारिक रोजगार में लगातार कमी आ रही है, केवल 23 प्रतिशत गैर—कृषि वेतन वाली नौकरियों को औपचारिक माना जाता है।

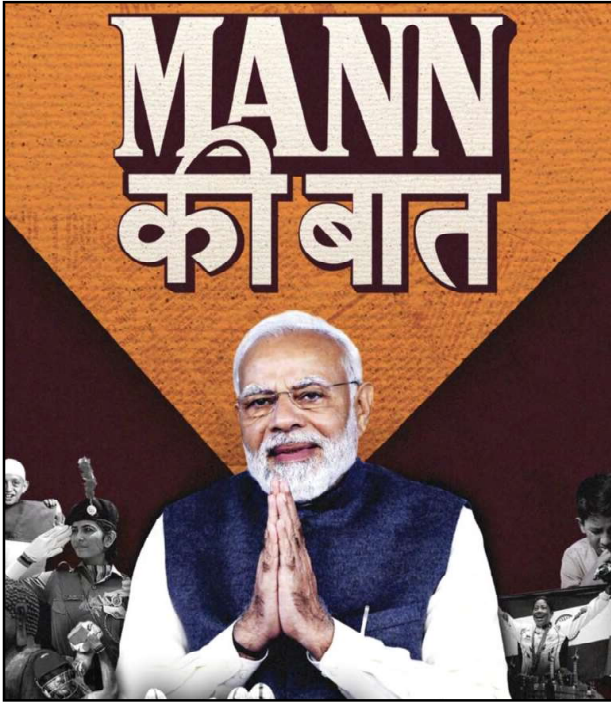
**आगे की राह**

भारत के अगले चरण में अनौपचारिक रोजगार की समस्या का समाधान, रोजगार बाज़ार में कौशल की कमी को दूर करना, लैंगिक असमानता को कम करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी न फैल जाए। आर्थिक लचीलापन केवल विकास दर पर ही नहीं, बल्कि उस विकास की स्थिरता और निष्पक्षता पर भी निर्भर करेगा। संक्षेप में, विश्व बैंक की रिपोर्ट के आँकड़े भ्रम नहीं, बल्कि मील के पथर हैं। भारत ने अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में वास्तविक प्रगति की है। अब, आगे का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि इन उपलब्धियों को न केवल संरक्षित रखा जाए, बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचाया जाए जो अभी भी पीछे छूट गए हैं। □□

(लेखिका—पीएच.डी. शोधाधी, युक्त गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, ईमेल: channukumari06@gmail.com)

मन की बात, १२४वें अंक में

# प्रधानमंत्री ने की स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आने और नवाचार शुरू किए जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल के माध्यम से ही हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने और स्थानीय व्यवस्थाओं का समर्थन करने का आग्रह भी किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड को संबोधित करते हुए देश में वैज्ञानिक संस्कृति के साथ-साथ स्वदेशी उत्पादन और खेल को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मुख्य स्तंभ बताते हुए समर्पण के साथ आगे आने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत में विज्ञान से लेकर आत्मनिर्भर भारत और आजादी की लड़ाई से लेकर देशभर के विरासत की बात की। उन्होंने कहा कि जबसे चंद्रयान-तीन की सफल लैंडिंग हुई है, तब से देश में विज्ञान को लेकर

एक नया माहौल है। देश के छात्रों में विज्ञान को लेकर एक नई जिज्ञासा जाग उठी है। हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमेस्ट्री ओलंपियाड और ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल हासिल किया है। यह देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि यूनेस्को ने 12 धरोहर किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता दी है। यह सभी हमारे देश के ऐतिहासिक किले हैं, जो विभिन्न घटनाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में मौजूद किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, सभी देशवासियों को इन पर गर्व करना चाहिए तथा अपने इतिहास को जानने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनगिनत बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली है, आजादी के दीवानों ने अपने रक्त से स्वतंत्रता संग्राम को सींचा था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत को दुनिया में विकसित बनाने के लिए हम सभी देशवासी एक सोच के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है। वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का सबसे मजबूत आधार है।

बातचीत के क्रम में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी आंदोलन तथा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और हथकरघा क्षेत्र की सफलताओं पर भी विशेष रूप से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को एक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता की वकालत करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि अगर देश को तरक्की करनी है तो हमें अपने ही देश के उत्पादों पर भरोसा करना होगा।  
— स्वदेशी संवाद

कहा गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोग विदेशी सामान का इस्तेमाल बंद करें और अपने देश में बने हुए सामान खासकर हाथ से बने कपड़ों का उपयोग करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिली और लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना जगी थी। मालूम हो कि इस आंदोलन की याद में भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे आजादी के लड़ाई के समय स्वदेशी कपड़े ने आंदोलन को एक नई ताकत दी थी, वैसे ही आज जब हमारा देश विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है तो कपड़ा उद्योग देश की एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। पिछले 10 सालों में देश के अलग-अलग हिस्सों में इस क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों ने अपनी मेहनत से अनेक कामयाबी की कहानी लिखी है। हमारे देश के कर्मवीरों ने न सिर्फ अपने लिए रोजगार बनाया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है।

बातचीत के क्रम में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पैटण गांव, उड़ीसा के मयूरभंज एवं उत्तर प्रदेश के कार्लींजर के कर्मवीरों का जिक्र किया और कहा कि वहां के लोगों के प्रयासों से उनके इलाकों की जिंदगियों में बड़ा बदलाव आया है।

उन्होंने दोहराया कि यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने बताया कि इन्हीं में से एक साल्हेर के किले में मुगलों की हार हुई थी। शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। खंडेरी में समुद्र के बीच किला है। दुश्मन शिवाजी को रोकना चाहते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। उन्होंने कहा कि इनमें से एक उत्तर प्रदेश के बांदा में कार्लिंजर किले पर महमूद गजनवी ने कई बार हमला किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली।

प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को भी आदर के साथ याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूं तो अगस्त का महीना क्रांति का महीना होता है क्योंकि इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी महीने में बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि भी होती है। अगस्त महीने के 15 तारीख को देश की आजादी मिली थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसी महीने में देश को बंटवारे की टीस भी मिली थी। यही कारण है कि हम हर साल 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका दिवस' के रूप में याद करते हैं।

प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम् मिशन जिसमें भारत की पुरानी पांडुलिपियां डिजिटल की जानी है, का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में एक

नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जहां से दुनिया भर के छात्र और शोधार्थी भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा यह सिर्फ कागज नहीं भारत की आत्मा के पन्ने हैं जिन्हें हमें नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता की वकालत करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि अगर देश को तरक्की करनी है तो हमें अपने ही देश के उत्पादों पर भरोसा करना होगा। वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारा नहीं, एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को अगर सही ढंग से उठाया जाए तथा जमीनी स्तर पर काम किया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती के साथ शामिल होगी। □□

## नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, दीर्घकालिक योजना और विद्युत आपूर्ति प्रबंधन पर फोकस

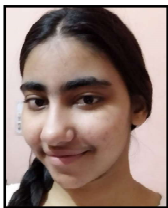
भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने और 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने के प्रधानमंत्री के विज़न को समर्थन देते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने एसईसीआई और एसजेवीएन (भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ) से 3300 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को मंजूरी दी है। यह खरीद दीर्घकालिक बिजली बिक्री अनुबंध के तहत भारत सरकार की योजना में की गई है। राज्य सरकार ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए इस खरीद की अनुमोदित क्षमता के लिए एमपीईआरसी से मंजूरी प्राप्त कर ली है। इस ऊर्जा पर 50 प्रतिशत आईएसटीएस ट्रांसमिशन शुल्क माफ होगा, जिससे यह विकल्प बेहद किफायती होगा। यह पहल राज्य को आरपीओ की पूर्ति और उपभोक्ताओं पर मूल्य भार घटाने में सहायक बनेगी। इसका उद्देश्य 2029-30 तक राज्य की बढ़ती ऊर्जा माँग को पूरा करना और विभिन्न स्रोतों से हरित ऊर्जा की पर्याप्त व्यवस्था करना है।

इस प्रस्ताव में 800 मेगावाट पवन ऊर्जा, 1290 मेगावाट सौर ऊर्जा (पीएम-कुसुम योजना), 252 मेगावाट जलविद्युत (दिबांग परियोजना) और 3300 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा (एसईसीआई व एसजेवीएन के माध्यम से) की खरीद शामिल है। 2029-30 तक एमपीपीएमसीएल को कुल 28.13 प्रतिशत आरपीओ लक्ष्य हासिल करना है। इसके लिए सरकार द्वारा गठितआयोग ने मसौदे के अधिकांश बिंदुओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, लेकिन पिछली अपूर्ण आरपीओ को अगले वर्षों में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी। साथ ही, बीईएसएस परियोजनाओं को भविष्य की ऊर्जा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना है। यह आदेश न सिर्फ पारदर्शिता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि ऊर्जा नीति में अनुबंधों की मजबूती, समयबद्धता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व काफी महत्वपूर्ण हैं। —स्वदेशी संवाद □□

# कांटों भरी है महिला रेजिडेंट डॉक्टरों की राह

सभी सभ्य सामाजिक संस्कृतियों में चिकित्सकों के लिए अनन्य आदर का भाव होता है। भारतीय जन मानस चिकित्सकों में भगवान का दूसरा स्वरूप देखता है। कुछ एक गिनती के अपवादों को छोड़ दें तो सामान्यतया भारत में चिकित्सा का पेशा अत्यंत जवाबदेही का है और अधिकांश डॉक्टर इसके लिए दिन-रात तत्पर भी रहते हैं। मगर अफसोसजनक है बीमार को निरोग बनाने के संकल्प से अपने काम में लगे चिकित्सकों को भी बुरे लोगों द्वारा निशाना बनाया जाता रहा है। विशेष रूप से विषम परिस्थितियों में काम करने वाली महिला चिकित्सकों को क्रूर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोलकाता के आईजी मेडिकल कॉलेज की महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या का मामला अभी ठंड भी नहीं हुआ कि ग्रेटर नोएडा के शारदा मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा छात्रा का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। लगातार प्रकाश में आ रहे मामलों से यह लग रहा है कि भारत की महिला रेजिडेंट डॉक्टरों की राह कांटों भरी है। असुरक्षा, लैंगिक भेदभाव, कार्य जीवन संतुलन की कमी, यौन उत्पीड़न और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा उनके जीवन को और अधिक कठिन बनाता है।

भारत में लगभग 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं जिससे हर साल लगभग 120000 एमबीबीएस डॉक्टर और 7 हजार पीजी मेडिकल डॉक्टर पढ़कर निकलते हैं। पीजी स्टूडेंट्स को जूनियर डॉक्टर या जूनियर रेजिडेंट कहा जाता है। पीजी के बाद नौकरी पाने वालों को सीनियर रेजिडेंट कहा जाता है। यह वही रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो मोटे तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। अस्पतालों के अधिकांश कार्य भार उनके कंधों पर ही है। अस्पताल में सबसे अधिक काम का दबाव पीजी स्टूडेंट्स पर ही होता है। अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब तकनीशियन और अन्य किसी विभाग की कमी का खामियाजा भी इन्हीं पीजी स्टूडेंट्स को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि वह कैरियर के प्रवेश के स्तर पर होते हैं, इसलिए सब उनका अधिकतम शोषण करते हैं। उन्हें सभी का काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस कारण पीजी छात्रों का कार्य भार और कार्य के घंटे काफी बढ़ जाते



महिला रेजिडेंट डॉक्टरों  
के लिए कार्य और निजी  
जीवन के बीच संतुलन  
बनाना एक दोहरी जंग  
है।  
— वैदेही



**महिला रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना एक दोहरी जंग है। मेडिकल शिक्षा का लंबा समय परिवार शुरू करने की उम्र के साथ टकराता है। ७० प्रतिशत महिला डॉक्टर घरेलू काम और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाती हैं। गर्भावस्था और स्तनपान जैसे चरण इस बोझ को और बढ़ाते हैं।**

हैं। उन्हें लगातार काम करने के लिए मजबूर भी किया जाता है।

हालिया घटनाएं भयावह हैं। ग्रेटर नोएडा के शारदा मेडिकल कॉलेज की छात्रा ज्योति शर्मा ने हॉस्टल के कमरे में अपनी जान दे दी। आरोप है कि विभाग के प्रोफेसर द्वारा छात्र को लगातार उत्पीड़ित किया जा रहा था। यह भी आरोप है कि प्रोफेसर ने परीक्षा से पहले प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया तथा चप्पल से मारने की धमकी देकर अपने कार्यालय से भगा दिया था। कॉलेज का कहना है कि छात्रा ने खुदकुशी की है जबकि परिवरीजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 2024 में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर से रेप-हत्या की घटना हुई थी, जिसकी जांच जारी है। वह लगातार 36 घंटे की ड्यूटी के बाद थक-हार कर सेमिनार रूम में ही सो गई थी।

बलात्कारी-हत्यारे से बचाव की कोशिश तो दूर, चीख कर मदद मांगने लायक भी नहीं रह गई थी। उस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 36 घंटे की ड्यूटी को अमानवीय कहा था। इसके बावजूद आज भी महिला

रेजिडेंट डॉक्टरों को लगातार ऐसी ड्यूटी करनी पड़ रही है।

यह भयावह है। रात की गहराई में जब अस्पतालों के गलियारे सुनसान हो जाते हैं, महिला रेजिडेंट डॉक्टरों को डर के साए में काम करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कई महिला डॉक्टर इतनी डरी होती हैं कि डॉक्टर रूम में विश्राम करने से भी कतराती हैं। वे कुर्सियों पर रात काटती हैं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें। एक स्टडी के अनुसार भारत में एक-तिहाई महिलाएं शारीरिक हिंसा का शिकार होती हैं। अस्पतालों में यह जोखिम और बढ़ जाता है। सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव उनकी जिंदगी को जोखिम में डालता है। समय आ गया है कि उनके लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं।

लेकिन ताज्जुब है कि एनएमसी ने पीजीएमईआर, 2023-24 में महिला रेजिडेंट डॉक्टरों की विशेष जरूरतों की पहचान करने और उनके अनुसार विशेष प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी है। मातृत्व मामले में अवश्य कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन पुरुष केंद्रित समाज में सुरक्षित और सहज कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप कोई प्रावधान अब तक नहीं करना संवेदनहीनता की निशानी है। पुरुष-प्रधान चिकित्सा क्षेत्र में महिला डॉक्टरों को हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया में केवल 12.5 प्रतिशत सदस्य महिला हैं। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 33 प्रतिशत है। मरीज अक्सर पुरुष डॉक्टरों को प्राथमिकता देते हैं। 78 प्रतिशत महिला सर्जन कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव का शिकार होती हैं। इसमें यौन-केंद्रित टिप्पणियां और मीम्स

शामिल हैं। यह भेदभाव उनकी प्रगति को रोकता है।

महिला रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना एक दोहरी जंग है। मेडिकल शिक्षा का लंबा समय परिवार शुरू करने की उम्र के साथ टकराता है। 70 प्रतिशत महिला डॉक्टर घरेलू काम और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाती हैं। गर्भावस्था और स्तनपान जैसे चरण इस बोझ को और बढ़ाते हैं। 36 घंटे की शिफ्ट और नींद की कमी उन्हें शारीरिक-मानसिक रूप से थका देती है। समाज की अपेक्षाएं कि वे घर और अस्पताल, दोनों संभालें, उनकी जिंदगी को और जटिल बनाती हैं। कई बार दबाव इतना बढ़ जाता है कि कुछ अपनी जिंदगी तक को अलविदा कह देती हैं। उन्हें मानसिक उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। विभागाध्यक्ष द्वारा अनुचित व्यवहार आम है। लेकिन प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए आवश्यक 'कंप्लीशन सर्टिफिकेट' के दबाव में शिकायतें दब जाती हैं। विभागाध्यक्ष शिकायतों को खारिज करते हुए कहते हैं, 'हमने भी तो यही झेला था।' यह चुप्पी उनकी आत्मा को तोड़ती है।

सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव भी बड़ी समस्या है। महिला रेजिडेंट डॉक्टर के लिए अलग रूम का अभाव है। रात की ड्यूटी में सुरक्षित आवागमन एक सपना है। ये कमियां न केवल उनकी सुविधा, बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाती हैं। महिला रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा और कार्य-जीवन संतुलन के लिए सहायक ढांचा जरूरी है। इन स्वास्थ्य नायिकाओं को सशक्त करने के लिए प्रणालीगत बदलाव अनिवार्य है। समाज का कर्तव्य है कि इन नायिकाओं को वह सम्मान और सुरक्षा दे जिसकी वे हकदार हैं। क्या हम उनके लिए खड़े होंगे? □□

## स्वदेशी जागरण मंच का गुवाहाटी में प्रांत विचार वर्ग हुआ संपन्न



स्वदेशी के जागरण हेतु देश भर में कार्य कर रहे स्वदेशी जागरण मंच की उत्तर असम प्रांत इकाई का दो दिवसीय विचार वर्ग रविवार को गुवाहाटी के पांडूनाथ देवालय मंदिर में संपन्न हुआ। विचार वर्ग में गुवाहाटी सहित उत्तर असम के 7 जिलों का प्रतिनिधित्व रहा।

मंच के अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख अन्नदा शंकर पाणिग्रही ने कहा कि वर्तमान में हमें स्वावलंबी होने की नितांत आवश्यकता है और इस आवश्यकता को केवल स्वदेशी के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। स्व के भाव का जागरण जन-जन में हो यह कार्य स्वदेशी जागरण मंच आगामी वर्ष में करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी स्व संस्कृति, स्व भाषा, स्व वेशभूषा, स्व भेषज, स्व भोजन सहित देश को समृद्ध करने के लिए स्व तकनीकी, स्व इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा।

विचार वर्ग के समापन सत्र में आगे बोलते हुए पाणिग्रही ने कहा कि वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की ताकत स्वदेशी पर ही निर्भर है। जितना हम स्वदेशी का विकास करेंगे उतना ही हम पूरे विश्व में शक्तिशाली होंगे और दुनिया जानती है कि हमारी शक्ति विनाश के लिए नहीं विकास के लिए होती है।

विचार वर्ग को स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉ धर्मेंद्र दुबे ने भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है जो सभी की उन्नति की कामना करती है। शांति का मार्ग यदि कोई पूरे विश्व को दिखा सकता है तो वह केवल भारतीय संस्कृति ही है। विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनियां जब भारत में अपना व्यापार बढ़ा रही हैं ऐसे में हमारे छोटे उद्योग एवं छोटी इकाइयों के बढ़ावे के लिए हर भारतीय को आगे आना होगा। भारतीय कंपनियों के सामानों को पर्याप्त मात्रा में हम

भारतीय अगर खरीदना शुरू करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास ही नहीं होगा अपितु हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार, उद्यमिता स्वाभाविक रूप से बढ़ती चली जाएगी और यही भारतीय विकास के मॉडल का प्रतिमान है।

मंच के प्रांत संयोजक प्रो तारणि डेका ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत विचार वर्ग से "स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान" को असम में शुरू किया गया।

इसके अंतर्गत स्वदेशी एवं विदेशी सामानों की सूची का निर्माण असमिया भाषा में किया जाएगा जिसे असम के गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य होगा। वहीं इस अभियान के अंतर्गत असम में स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले सामानों की सूची भी तैयार की जाएगी।

विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समान को अमेजॉन पिलपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म द्वारा धड़ल्ले से बेचकर भारत के बाजारों को कमजोर किया जा रहा है, उसके खिलाफ जन जागरण का कार्य भी इस अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। इन विदेशी प्लेटफॉर्म से खरीददारी का विरोध करते हुए प्रांत विचार वर्ग में नारा दिया गया कि "अब से बाजार जाएंगे, सामान स्वदेशी लाएंगे।"

इस अभियान के अंतर्गत गुवाहाटी सहित असम के प्रमुख जिला एवं कस्बों के बाजारों में अधिक से अधिक स्वदेशी कॉर्नर बनाने के लिए भी अपील की गयी। शीघ्र ही 'स्वदेशी शंखनाद' कार्यक्रम आयोजित कर अभियान का बिगुल बजेगा और चाइनीज एवं बंगलादेश सहित विदेशी समान के बहिष्कार का जनजागरण इस अभियान में किया जाएगा।

मंच प्रांत सह संयोजक अर्जुन बर्मन ने बताया कि विचार वर्ग में स्वदेशी अपनाने, विदेशी एवं चाइनीज, तुर्की व अजरबैजान का बहिष्कार करने, देश को समृद्धशाली बनाने में अपना योगदान स्वदेशी के माध्यम से करने तथा उद्यमिता स्वरोजगार को प्रतिस्थापित करने के लिए सामूहिक स्वदेशी शपथ ली गई। विचार वर्ग में यह भी तय किया गया कि इस सामूहिक शपथ कार्यक्रम को गुवाहाटी के हर नगर,मोहल्ले में आयोजित किया जाएगा।

विचार वर्ग को प्रांत प्रचार प्रमुख बिस्वजीत बर्मन, नागालैंड से आयी प्रांत महिला प्रमुख अनीता रॉय चौधरी, कोष प्रमुख सी ए अरुण चौधरी, स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक लघुद्योग भारती के पार्थप्रतिम पाठक, गीतीमा डेका, सहित महानगर इकाई के संयोजक अनल राय ने भी संबोधित किया। वर्ग के उद्घाटन में भारतीय सेना की पूर्वोत्तर की प्रथम महिला (पूर्व मेजर) तृप्ति कोना मजूमदार ने स्वदेशी की आवश्यकता पर बल दिया। वर्ग का संचालन विभाग संगठक जयदीप राय ने किया।

## हर घर तक पहुंचेगा स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान



भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचकूला में स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबी भारत अभियान चलाया जाएगा। यह निर्णय भारत विकास परिषद भवन में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में 20 से ज्यादा संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। स्वावलंबी भारत अभियान के उत्तर क्षेत्र समन्वयक डॉ. राजेश गोयल ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापार युद्ध भारत के लिए बड़ा खतरा है। इससे निपटने का एकमात्र रास्ता स्वदेशी है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच लंबे समय से इस विषय पर काम कर रहा है। अब प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। डॉ. गोयल ने बताया कि विदेशी कंपनियों का विरोध करने के लिए सभी व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संगठनों ने एकजुट होकर आग्रह किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की, अजरबैजान, चीन और अमेरिका के खिलाफ लोगों में स्वाभाविक आक्रोश है। अमेरिकी टैरिफ, चीनी डंपिंग और पाकिस्तानी आतंकी घटनाओं के चलते पूरे देश में 'विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ' अभियान की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि देश के 50 से ज्यादा संगठनों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 12 जून को दिल्ली में शंखनाद कार्यक्रम के जरिए इस अभियान की शुरुआत हुई। अब यह अभियान पंचकूला जिले के हर गांव, मोहल्ले और घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सभी संगठनों से सहयोग मांगा गया है। डॉ. गोयल ने अपील की कि हर गांव, स्कूल, कॉलेज और मोहल्ले में छोटी-छोटी बैठकें, कार्यक्रम, सेमिनार और संकल्प सभाएं आयोजित की जाएं। इनमें स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आग्रह किया जाए। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के जयघोष के साथ भारत को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया जाए। इससे 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा भी मिलेगा। यह अभियान 'मेक इन इंडिया' की भावना को जमीनी स्तर पर ले जाएगा, जिससे हर नागरिक 'मैं अपने देश में निर्मित उत्पादों के उपयोग और उन पर गर्व करने की भावना विकसित होगी।

इससे सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी होगा, जैसे कई स्वदेशी उत्पाद हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हैं, इस अभियान से इन शिल्पों और कलाओं को जीवित रखने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

## स्वदेशी जागरण मंच की बैठक में कार्यक्रमों पर मंथन

स्वदेशी जागरण मंच कानपुर प्रांत का दो दिवसीय विचार वर्ग भानी देवी गोयल इंटर कलेज में आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्याम बिहारी गुप्ता, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, सह संगठक श्री सतीश कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह श्री रामकेश, विभाग संघचालक शिव कुमार भार्गव जी विभाग प्रचारक मनोज, धर्माचार्य हरिओम पाठक, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला, केट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय पटवारी, उप्र उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष ब्रज बिहारी सोनी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान आगामी कार्यक्रमों को रेखांकित करते हुए अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने बताया कि देश में 50 से अधिक संगठनों के साथ मिलकर स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबी अभियान चलाया जायेगा। सम्पूर्ण नागरिकों को विदेशी विषेककर चीनी, अमरीकी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया जायेगा। उद्घाटन सत्र का संचालन डा पीयूष नायक ने किया। स्वदेशी जागरण मंच के विभिन्न सत्रों में विभिन्न जिलों से आये वक्ताओं ने अपने विषय रखे। वर्ग में प्रवीण मिश्रा, सुदीप खरे, जयकिशन प्रेमानी, डा मुन्ना तिवारी, लाल सिंह हाकीम सिंह, जसमेजय सिंह, रणवीर सिंह राकेश कुशवाहा, शुभम अग्रवाल शील कोपरा राहुल तिवारी, प्रदीप गुप्ता, सुनील अग्रवाल अशोक अग्रवाल अशोक विलगाईया, अरुणा बिलगाईया, प्रीती नेवालकर, स्वप्निल मोदी, शीतल सेंगर रश्मी सविता, वासुधा प्रेमानी, माला महरोत्रा उपस्थित रहे।

## 'स्वदेशी अपनाओ-ऑनलाइन विदेशी भगाओ'

स्वदेशी जागरण मंच, गोड्डा द्वारा महागामा में आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जन-जन में स्वदेशी अपनाने की भावना पैदा करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत संयोजक राजेश कुमार उपाध्याय, प्रांत पूर्णकालिक हिमांशु शेखर, जिला संयोजक अजय चौबे, जिला पूर्णकालिक मोनू दूबे, चेम्बर्स ऑफ कामर्स के उपाध्यक्ष मोहन केसरी, प्रभुनाथ भगत, शशिकांत जयसवाल, नितिश

मोदी, अमर मोदी, अमित जायसवाल, मंगल मोदी एवं प्रबुद्ध व्यवसायिक बंधु और नागरिकों सहभागी रहे।

कार्यक्रम में राजेश कुमार उपाध्याय ने कहा की स्वदेशी वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को भी संरक्षित करने में मदद करता है। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने से देश के भीतर उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलते हैं। मोहन केसरी ने कहा ऑनलाइन खरीदारी कम करने और लोकल सामान खरीदने के कई फायदे हैं। लोकल सामान खरीदने से स्थानीय व्यवसायों और उत्पादकों को समर्थन मिलता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लोकल सामान खरीदने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। लोकल सामान अक्सर ताजगी और गुणवत्ता के मामले में बेहतर होते हैं। लोकल सामान खरीदने से परिवहन की आवश्यकता कम होती है, जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। इस कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए अजय चौबे ने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी कम करने और लोकल सामान खरीदने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद करता है। उन्होंने आह्वान किया कि आईए, हम सब मिलकर लोकल सामान खरीदने का समर्थन करें और अपने समुदाय को मजबूत बनाने में योगदान दें।

## विदेशी कंपनियों के शोषण से बचें: महामहिम राज्यपाल

बिहार विधान परिषद के सभागार में स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के तत्वावधान में 'स्वदेशी शंखनाद' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेक इन इंडिया और मेक इन बिहार अभियान को लेकर विशेष चर्चा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में युवाओं, उद्यमियों और नीति-निर्माताओं की भूमिका पर बल दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कमजोर और गरीब देशों का शोषण करने वाली मल्टी नेशनल कंपनियों से बचना चाहिए। स्वदेशी केवल आर्थिक विचार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की सांस्कृतिक चेतना है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार हाल के दिनों में स्वदेशी के एक प्रमुख उत्पादन केंद्र

के रूप में उभर रहा है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने उद्योग जगत में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की बात कही। मंच संचालन डॉ प्रवीण पटेल ने किया। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक अरुण ओझा, अजय उपाध्याय, आरएसएस क्षेत्र कार्यवाह मोहन सिंह, मुकुंद मिश्रा, अशोक वर्मा, प्रिंस राजू, संगीता झा, उपेंद्र प्रसाद, डॉ संजीव सिंह, अमरेंद्र सिंह, संगीता झा, डॉ देवेश कुमार उपस्थित रहे।

## विचार वर्ग में लिया स्वदेशी अपनाने का संकल्प



स्वदेशी जागरण मंच गोरक्ष प्रांत द्वारा जागृति के बरपार स्थित बरगद सभागार में विचार वर्ग के अंतिम दिन शुक्रवार को स्वदेशी सुरक्षा व स्वावलंबन अभियान का शंखनाद किया गया। इसमें शामिल लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का उद्घोष करते हुए स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया।

पूर्वी यूपी क्षेत्र के संयोजक अनुपम श्रीवास्तव ने कहा स्वदेशी जागरण मंच जिले के व्यापारी, उद्योग, सामाजिक व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषांगिक संगठनों के साथ मिलकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए जिले भर में जन-जागरण अभियान चलाएगा। इस दौरान प्रांत समन्वयक ईश्वर चंद, बलिया के जिला संयोजक आनंद सिंह आदि उपस्थित रहे।

## चीन और तुर्की के सामानों के बहिष्कार का आह्वान

स्वदेशी जागरण मंच, जयपुर महानगर एवं सांगानेर इकाई की ओर से जगतपुरा में बैठक हुई। बैठक में प्रांत सह संयोजक लोकेन्द्र सिंह नरुका ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। इन देशों को करारा जवाब देने का सबसे सशक्त माध्यम है— उनके उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार हो। दिल्ली से शुरू हुए स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के तहत देश भर में जनजागरण किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य

देशवासियों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। गांव-गांव जाकर स्थानीय व्यापारियों को स्वदेशी उत्पाद बेचने का संकल्प भी दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक प्रमुख डॉ. धर्मवीर चंदेल, दिनेश चंद शर्मा, प्रांत कोष प्रमुख ओमप्रकाश कुमावत, विभाग सह संयोजक रामप्रसाद शर्मा, महानगर संयोजक शंभूसिंह राजावत व डॉ. योगेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

## ‘बेरोजगारी दूर करने को कुटीर उद्योग को बढ़ावा जरूरी’

स्वदेशी जागरण मंच जयपुर प्रांत की ओर से विचार वर्ग एवं कार्यशाला का आयोजन समिधा भवन भरतपुर में किया गया। संघ चालक महेन्द्र सिंह मग्गो, प्रांत प्रचारक बाबूलाल, मुख्य अतिथि सरदार हिरासिंह, अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख राजीव कुमार, डॉ. धर्मेन्द्र दुबे, क्षेत्र संयोजक सतीश आचार्य, प्रांत संयोजक सुरेंद्र नामा, प्रांत समन्वयक लोकेंद्र सिंह नरुका ने भारत माता, दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का प्रारम्भ किया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता बाबूलाल जी ने कहा कि देश को स्वदेशी उत्पादों को आम जन तक पहुंचाने लिये मंच के प्रांत कार्यकर्ता स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान चलाकर आम जनता के बीच अलख जगाना है जिससे आमजन स्वदेशी उत्पादों को खरीद कर उपयोग करें, जिससे देश विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था को बन सके। कार्यशाला के मुख्य अतिथि सरदार हीरा सिंह ने कहा कि देश में बेरोजगारी दूर करने के लिये एकमात्र उपाय कुटीर उद्योग धंधों पर ध्यान देना होगा। युवा बेरोजगार सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए कुटीर उद्योग लगाएं जाये। जिससे युवा वर्ग रोजगार युक्त हो और अपनी आजीविका चलाने में स्वावलंबी बने। जयपुर प्रांत संघचालक महेन्द्र सिंह मग्गो ने कहा कि स्वावलंबी भारत अभियान के कार्यक्रम को पूर्णतय सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर रोजगार सृजन कार्यालय खुलवाना अति आवश्यक है।

कार्यशाला को स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख धर्मेन्द्र दुबे, अखिल भारतीय विचार प्रमुख डा. राजीव कुमार, क्षेत्र संयोजक सतीश आचार्य, क्षेत्र समन्वयक अनिल वर्मा, प्रांत संयोजकसुरेन्द्र कुमार नामा, प्रांत मन्वयक लोकेंद्र सिंह नरुका, विभाग संयोजक सतीश दीक्षित ने संबोधित किया। इस मौके पर राकेश शर्मा, त्रिलोक शर्मा, बलराम बघेल, योगेश दीक्षित, विजय श्रीवास्तव, ओम प्रकाश

कोली, भीमसेन कुशवाह, लाखन सिंह, शुभनेश पाराशर, सचिन मित्तल, नरेंद्र बघेल, भागीरथ सिंह, शिवचरण, मेवाराम सैनी, चेतन मीणा, विनीता सिंह, दीप्ति पाराशर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच संचालन प्रांत सहसंयोजक विनोद पाल यादव एवं जिला प्रचार प्रमुख शुभनेश पाराशर ने किया।

## रैली निकाली, स्वदेशी अपनाने का किया आह्वान

स्वदेशी जगरण जयपुर प्रांत का दो दिवसीय प्रचार वर्ग 14- 15 जून को संविदा भवन संघ कार्यालय जवाहर नगर में हुआ। विचार वर्ग में 9 सत्रों में स्वदेशी सुरक्षा, स्वावलंबन अभियान, सशक्त समर्थ भारत का आधार स्वदेशी एवं स्वावलंबन, जिला स्वावलंबन टीम 11, जिला पूर्ण कालिक की भूमिका एवं व्यवस्थाए जिला स्वावलंबन केन्द्र युवाओं के लिए स्वरोजगार का माध्यम, राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी एवं स्वदेशी की विकास यात्रा कार्यकर्ता दायित्व बोध एवं संगठन रचना, स्वदेशी मेले, एक जिला एक उत्पाद, स्थानीय उत्पाद, राजस्थान में महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर, भारतीय संस्कृति, परिवार और मात्र शक्ति स्वदेशी की भावनाए स्वदेशी की ओर बढ़ती नारी शक्ति, स्वावलंबन में युवा जनसंख्या की भूमिका, स्वदेशी में मीडिया की भूमिका, प्रचार-प्रसार पर विभिन्न सत्रों में डॉ. राजीव कुमार अ.भा विचार प्रमुख, डॉ. धर्मेन्द्र दुबे अ. भा. प्रचार प्रमुख, डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी अ. भा. संपर्क प्रमुख, डॉ. सतीश आचार्य क्षेत्र संयोजक, अनिल वर्मा क्षेत्र विभाग प्रमुख, सुदेश सैनी क्षेत्र प्रचारक प्रमुख, सुरेंद्र कुमार प्रांत संयोजक लोकेंद्र सिंह नरुका प्रांत समन्वयक, विनोद पाल एवं धर्मेन्द्र शर्मा ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण एवं प्रबोधन दिया।

समारोह सत्र में विभाग संयोजक सतीश दीक्षित ने आभार जताया। स्वदेशी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम 6 बजे बिजली घर चौराहे से कुम्हेर गेट तक उद्घोष के साथ शहर के प्रमुख बाजारों से रैली निकालकर व्यापारी एवं आमजन में वस्तुओं के क्रय-विक्रय एवं उपभोग के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर संरक्षक शिवचरण पीतलिया प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कुलभान सिंह, विभाग संयोजक सदस्य त्रिलोकी शर्मा, जिला संयोजक शिवकुमार शर्मा, सह संयोजक बलराम सिंह, संघर्ष वाहिनी प्रमुख विष्णु शर्मा, युवा प्रमुख नरेंद्र बघेल, महिला प्रमुख प्रमुख कैप्टन सचिन मित्तल, नगर विनीता सिंह, शिव चरण सैनी, देवेन्द्र उपस्थित रहे। संचालन जिला प्रचार प्रमुख चामड़ एवं भीम सिंह एडवोकेट शुभनेस पाराशर ने किया। □□

स्वदेशी गतिविधियां

# प्रांतीय विचार वर्ग

सचित्र झलक



गोरखा



त्रिपुरा



जिला सम्मेलन, जमशेदपुर (झारखंड)



महाकौशल बैठक



स्वदेशी गतिविधियां

# प्रांतीय विचार वर्ग

सचित्र झलक



हरियाणा



मेरठ



उत्तराखंड



कानपुर



प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022 से प्रकाशित, संपादक: अजेय भारती